अप्रैल-मई, 2026, वर्ष-34, अंक-12

उत्तर प्रदेश संदेश

मां गंगा-सा विस्तार, सुख-समृद्धि अपार

गंगा एक्सप्रेसवे

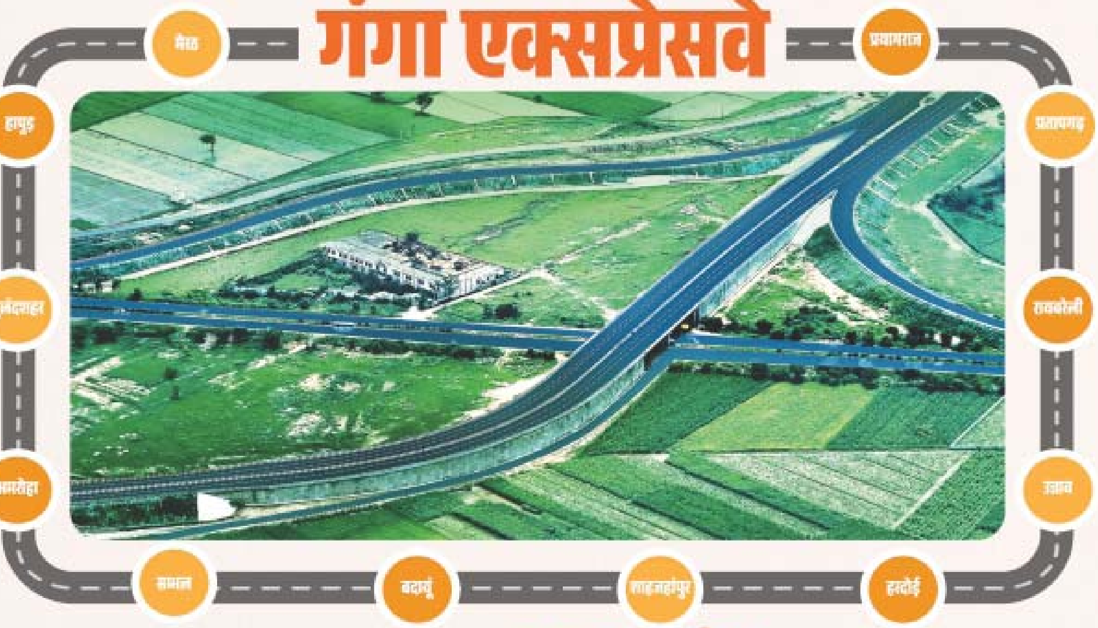

₹36,230 करोड़

से निर्मित उत्तर प्रदेश के सबसे विराट

594 कि.मी. लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ-प्रयागराज) का

लोकार्पण

प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी

के द्वारा

सम्पन्न हुआ

विस्तार भी-रफ्तार भी : 6 लेन वाले (8 लेन में विस्तारणीय) गंगा एक्सप्रेसवे से 12 जनपद आच्छादित • डिजाइन स्पीड 120 कि.मी./घंटा, मेरठ से प्रयागराज की दूरी 6 से 8 घंटे में होगी पूरी • हापुड़ में गंगा नदी पर 960 मीटर एवं बदायूं में रामगंगा नदी पर 720 मीटर का दीर्घ सेतु • मेरठ एवं प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा सहित कुल 21 रैम्प इंटरचेंज • पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम • लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग एवं टेक-ऑफ हेतु शाहजहांपुर के समीप 3.50 कि.मी. लम्बी हवाई पट्टी • एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 3.75 मी. चौड़ी स्टैण्डर्ड सर्विस लेन

विकास भी-कल्याण भी : फ्यूल एवं ई-चार्जिंग सुविधा के साथ 9 विशाल जन-सुविधा परिसर • गंगा एक्सप्रेसवे के 12 जनपदों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास का कार्य गतिमान • औद्योगिक इकाइयों एवं कृषि उत्पादन क्षेत्रों की दिल्ली से तीव्र कनेक्टिविटी • कृषि, वाणिज्य, पर्यटन एवं औद्योगिक आय में होगी वृद्धि • दुग्ध, सब्जी, फल के भंडारण एवं प्रसंस्करण के नवीन केंद्र खुलेंगे • व्यापार एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा • नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण एवं मेडिकल संस्थानों के लिए असीम संभावनाएं

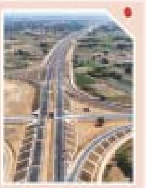

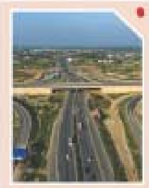

गरिमामयी उपस्थिति

आनंदीबेन पटेल | **योगी आदित्यनाथ**
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश | मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

पंकज चौधरी — राज्य मंत्री, वित्त, भारत सरकार
जितिन प्रसाद — राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग, भारत सरकार
केशव प्रसाद मौर्य — उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
ब्रजेश पाठक — उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

सुरेश कुमार खन्ना — मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' — मंत्री, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन.आर.आई. तथा निवेश प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश

एवं अन्य गणमान्य महानुभाव

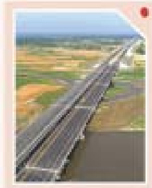

दिनांक : 29 अप्रैल, 2026 | स्थान : मल्लावां कट, निकट चैनेज 351 कि.मी. गंगा एक्सप्रेसवे, तहसील - बिलग्राम, जनपद - हरदोई, उ.प्र.

सुपरफास्ट प्रदेश- उत्तर प्रदेश : 8 एक्सप्रेसवे संचालित, 14 विकास के विभिन्न चरणों में • देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55% भाग उत्तर प्रदेश में मौजूद • एक्सप्रेसवे के आसपास 26 जनपदों के 27 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर • औद्योगिक विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का क्रियान्वयन • पीएम गति शक्ति को लागू करने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश • अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज एवं आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापना का कार्य गतिमान • ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी (उत्तर प्रदेश) में स्थित • देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में (16,000 किलोमीटर) • 17 एयरपोर्ट संचालित (5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट), 7 विकास के विभिन्न चरणों में • राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (वाराणसी-हल्दिया) के अयोध्या तक विस्तार का कार्य प्रगति पर

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

अप्रैल, मई-2026, वर्ष-34, अंक-12

उत्तर प्रदेश

संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :

संजय प्रसाद

प्रमुख सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :

विशाल सिंह

सूचना निदेशक

सम्पादकीय परामर्श :

अरविन्द कुमार मिश्र

अपर निदेशक, सूचना

चन्द्र विजय वर्मा

सहायक निदेशक (प्रकाशन)

दिनेश कुमार गुप्ता

उपसम्पादक, सूचना

अजय कुमार द्विवेदी

सहयुक्त संपादक

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ

ईमेल : upsandesh20@gmail.com

दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 9412674759, 7705800978

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

- मजबूत हुईं बुनियादी सुविधाएं — 3
  -वीरेंद्र नाथ भट्ट
- समावेशी विकास, डिजिटल सुशासन — 8
  -अक्षत कोहली
- सुमंगला से संवरते सपने — 14
  -डॉ. शिवानी कटारा
- नवाचार और विकास का संगम बनता यूपी — 17
  -डॉ. सुषमा गुप्ता
- स्पेशल-300 कसेगी अपराधियों की नकेल — 23
  -प्रद्युम्न तिवारी
- 8 हजार बढ़े मानदेय और खिल उठे चेहरे — 26
  -डॉ. सुयश नारायण मिश्रा
- सशक्त नारी विकसित राज्य — 31
  -मुकुल मिश्रा
- ‘बेसिक’ से ‘बेहतर’ की ओर बढ़ते कदम — 35
  -ऋचा सिंह
- अत्याधुनिक होते यूपी के शहर — 40
  -विमल पाठक
- किसानोन्मुख योगी सरकार — 42
  -अर्चना शुक्ला
- योगी सरकार की योजना से बदली तकदीर — 46
  -पायल लक्ष्मी सोनी
- उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्रांति की नई उड़ान — 49
  -देवराज सिंह
- यूपी के सपनों का गंगा एक्सप्रेस-वे — 52
  -सियाराम पांडेय ‘शांत’
- एआई सुपर पावर बनता उत्तर प्रदेश — 56
  -अजय श्रीवास्तव
- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हरित संकल्प — 60
  -सौम्या मिश्रा
- आर्थिक संबल बन रहा काला नमक चावल — 62
  -यशोदा श्रीवास्तव

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है और इसे आसान बना रहा है राज्य में बढ़ता सड़क संजाल। सरकार बनने के दिन से ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, वह बहुत तेजी के साथ मूर्त रूप धारण कर रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतिफल यह है कि अपराध को अंजाम देने से पूर्व अपराधी एक बार सोचते जरूर हैं। सरकार के तेवरों को भांप कर अपराधी या तो प्रदेश से पलायन कर गए हैं या फिर जेल के सींखचों में अपने गुनाहों पर पश्चाताप कर रहे हैं। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और अपराधी सिर न उठा सकें, इस निमित्त सरकार ने उन पर शिकंजा कसने का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। 'टीम स्पेशल-300' को इसी क्रम में देखा जा सकता है। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने 300 प्रशिक्षित क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए हैं।

साइबर और फॉरेंसिक तकनीकी का उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। फॉरेंसिक लैब की संख्या भी 12 कर दी गई हैं। वर्ष 2017 से पहले राज्य में केवल 2 फॉरेंसिक लैब हुआ करती थीं। चाहे कृषकों की आय बढ़ाने की बात हो या प्रदेश में औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की, योगी आदित्यनाथ हमेशा सजग रहे हैं। यह पहली सरकार है जिसने हर सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठकें की हैं और जनहित के मुद्दों पर प्रभावी मंथन किया है, यही वजह है कि सरकार में जनता से जुड़े फैसले धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। हाल के दिनों में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की मानदेय वृद्धि के मसले को कमोवेश इसी रूप में देख-समझा जा सकता है और अब तो सरकार की रीति-नीति को अन्य प्रदेशों में भी मानक के तौर पर लिया जा रहा है। यह यूपी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। वैसे भी सरकार जिस तरह आत्मनिर्भर भारत के विकास में यूपी ही नहीं, देश का ग्रोथ इंजन बन रही है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। विकास की पहली शर्त है विश्वास और सुरक्षा। कहना न होगा कि उत्तर प्रदेश इस कसौटी पर शत-प्रतिशत खरा उतरा है।

सम्पादक

मजबूत हुई बुनियादी सुविधाएं

—वीरेंद्र नाथ भट्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस–वे उद्घाटन समारोह में कहा था कि देश की सड़कें, हाइवे, एक्सप्रेस–वे, एयरवे, रेलवे और वाटर–वे विकास की भाग्य रेखाएं हैं और बीते एक दशक से हमारी सरकार इनके निर्माण में निरंतर प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश में भी 2017 से प्रदेश की भाग्य रेखा को संवारने और निखारने का काम द्रुत गति से हुआ है और जारी है।

2016–17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग ₹13.3 लाख करोड़ था। योगी आदित्यनाथ के सरकार दोनों कार्यकाल के कुल दस बजट पेश कर चुकी है और यह दसवां वर्ष है। इस 9 वर्षों में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ढाई गुने से अधिक बढ़ा है। 2025–26 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) मौजूदा कीमतों पर लगभग ₹36 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा राज्य की मजबूत आर्थिक वृद्धि और भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है। इस वृद्धि का मुख्य आधार बुनियादी ढांचा और कृषि क्षेत्र हैं, और यह 2024–25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 12 प्रतिशत की बढ़त को प्रदर्शित करता है।

फाइलों में अटकी योजनाएं, वर्षों तक लंबित अनुमतियां और विभागों के बीच तालमेल की कमी, कभी उत्तर प्रदेश की पहचान मानी जाने वाली ये समस्याएं अब बीते दौर की बातें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते है कि प्रो–एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति ने शासन की सोच, कार्यशैली और नतीजों तीनों को बदल दिया है। ''प्रगति' पोर्टल आज केवल समीक्षा तंत्र नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त प्रतीक बन चुका है। प्रगति मॉडल ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब दृढ़ इच्छाशक्ति, तकनीकी माध्यम और जवाबदेही एक मंच पर आती हैं, तो परिणाम अपने आप सामने आते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और सहकारी संघवाद के जरिए जटिल से जटिल परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से पूरा करना संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति मॉडल ने प्रदेश को देश का इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन बना दिया है। राज्य के पास

वर्तमान में 10.48 लाख करोड़ रुपये की 330 परियोजनाओं का देश का सबसे बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। इनमें से 2.37 लाख करोड़ की 128 परियोजनाएं पूरी होकर कमीशन हो चुकी हैं, जबकि 8.11 लाख करोड़ रुपये की 202 परियोजनाएं तय समय–सीमा के भीतर पूरी हो जाएंगी।

प्रगति पोर्टल के माध्यम से राजस्व, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर विकास सहित सभी संबंधित विभाग एक ही मंच पर बैठकर निर्णय ले रहे हैं। इससे अनुमतियों और स्वीकृतियों में अभूतपूर्व तेजी आई है और यूपी ''बाटलनेक'' राज्य से ''ब्रेकथ्रू'' राज्य में बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश ''फैसिलिटेटर'' नहीं, बल्कि ''एक्सेलेरेटर'' की भूमिका में है। प्रगति जैसे तकनीक–आधारित प्लेटफार्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को मजबूत किया है और विकास के साथ–साथ रोजगार सृजन को भी नई गति दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश वर्षों के संघर्ष और नीतिगत उदासीनता से मुक्त होकर 'बीमारू' श्रेणी से निकलकर भारत के विकास के इंजन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश ने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों और उपेक्षा पर काबू पाकर खुद को रूपांतरित किया है।

बकौल योगी आदित्यनाथ अयोध्या, काशी और मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और राज्य अव्यवस्था से उत्सव की ओर बढ़ रहा है।

अपार संभावनाओं की भूमि उत्तर प्रदेश आज वर्षों के संघर्ष और नीतिगत उदासीनता से आगे बढ़कर भारत के विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है।

2016–17 वित्तीय वर्ष के अंत तक, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 9,017 किलोमीटर थी और मार्च 2017 तक, राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 7,201 किलोमीटर थी। उत्तर प्रदेश में केवल 2 प्रमुख चालू एक्सप्रेस–वे थे (यमुना एक्सप्रेस–वे और आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे)।

–यमुना एक्सप्रेस–वे : 165.5 किमी (चालू)।

2016–17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग ₹13.3 लाख करोड़ था। योगी आदित्यनाथ के सरकार दोनों कार्यकाल के कुल दस बजट पेश कर चुकी है और यह दसवां वर्ष है। इस 9 वर्षों में प्रदेश का सकल घरेलु उत्पाद ढाई गुने से अधिक बढ़ा है। 2025–26 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) मौजूदा कीमतों पर लगभग ₹36 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा राज्य की मजबूत आर्थिक वृद्धि और भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है। इस वृद्धि का मुख्य आधार बुनियादी ढांचा और कृषि क्षेत्र हैं, और यह 2024–25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 12 प्रतिशत की बढ़त को प्रदर्शित करता है।

–आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे : 302 किमी

मार्च 2017 तक, उत्तर प्रदेश में पक्की सड़कों (जिनमें राष्ट्रीय राज मार्ग और राज्य मार्ग और जिला सड़कें शामिल हैं) की कुल लंबाई लगभग 3,83,488 कि.मी. तक पहुँच गई थी।

योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 2026 की शुरुआत तक, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन गया है। यहाँ 1,788 कि.मी. से ज्यादा एक्सप्रेस–वे चालू हैं या पूरे होने के करीब हैं, जिनमें गंगा एक्सप्रेस–वे और लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2,340 कि.मी. लंबा एक इंटीग्रेटेड कॉरिडोर विकसित कर रहा है, जो पूरे राज्य में कई इंडस्ट्रियल पार्कों और तेज गति वाले परिवहन को बढ़ावा देगा।

उत्तर प्रदेश में भारत की 50 प्रतिशत से अधिक एक्सप्रेस–वे लंबाई मौजूद है, और यह राज्य भर में 27 औद्योगिक पार्कों को सहयोग देने के लिए इस एक्सप्रेस–वे नेटवर्क का लाभ उठाएगा।

2026 की शुरुआत तक, राज्य के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे और यमुना एक्सप्रेस–वे सहित एक मजबूत नेटवर्क पर यातायात चल रहा है।

लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे–63 किलोमीटर लंबा, 6–लेन वाला यह एक्सप्रेस–वे लगभग पूरा हो चुका है और मई माह के अंत उदघाटन होने की संभावना है, जिससे यात्रा का समय घटकर लगभग 35 मिनट रह जाएगा।

गंगा एक्सप्रेस–वे–594 किलोमीटर लंबा, 6–लेन वाला यह प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है, जिससे एक्सप्रेस–वे की कुल लंबाई में काफी बढ़ोतरी हुई है।

नई परियोजनाएँ– 56 जिलों को जोड़ने के लिए कई नई परियोजनाएँ, जिनमें विंध्य एक्सप्रेस–वे (320 किमी) और कुल 866 किमी की अन्य परियोजनाएँ शामिल हैं, विकास के चरण में हैं।

–गाजियाबाद–कानपुर एक्सप्रेस–वे : 2026 तक इन दो औद्योगिक शहरों को जोड़ने वाला 380 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर।

–380 किलोमीटर लंबा गाजियाबाद–कानपुर एक्सप्रेस–वे 2026 के आखिर तक पूरा होने वाला है। इसका उद्देश्य इन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर लगभग 3.5 से 5.5 घंटे करना है। यह 4–लेन (जिसे 6–लेन तक बढ़ाया जा सकता है) वाला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 9 जिलों को आपस में जोड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स की क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

ऊर्जा–पूर्ववर्ती सरकारों के समय प्रदेश में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता मात्र 7,159 मेगावाट थी, जबकि आज उत्तर

प्रदेश अपने स्वयं के स्रोतों से 18,136 मेगावाट पावर जनरेशन क्षमता की ओर अग्रसर है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों का विस्तार नहीं, बल्कि प्रदेश की औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू जरूरतों की पूर्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। आज उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सोलर क्रांति

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने आम नागरिक को ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश ने इस योजना के अंतर्गत 1.29 गीगावॉट अथवा 1,299 मेगावाट सौर क्षमता अर्जित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब हर व्यक्ति ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है और सोलर ऊर्जा के माध्यम से न केवल बिजली प्राप्त कर सकता है, बल्कि अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकता है।

इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र में चर्चा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय था जब प्रदेश में बिजली की इतनी कमी थी कि लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे।

आज वही उत्तर प्रदेश 24 घंटे जिला मुख्यालयों पर, 22 घंटे तहसील मुख्यालयों पर और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी पीड़ा यह नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, बल्कि उनकी पीड़ा यह है कि अब बिजली क्यों आ रही है। क्योंकि अंधेरे में जो कारनामे होते थे, वे अब बंद हो गए हैं। प्रकाश व्यवस्था से पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हुई हैं।

1 अप्रैल, 2022 से वर्ष 2025–2026 के काल में कुल 2,410 नए 33/11 KV पावर सब–स्टेशन बनाए गए हैं और

योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 2026 की शुरुआत तक, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन गया है। यहाँ 1,788 कि.मी. से ज्यादा एक्सप्रेस–वे चालू हैं या पूरे होने के करीब हैं, जिनमें गंगा एक्सप्रेस–वे और लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2,340 कि.मी. लंबा एक इंटीग्रेटेड कॉरिडोर विकसित कर रहा है, जो पूरे राज्य में कई इंडस्ट्रियल पार्कों और तेज गति वाले परिवहन को बढ़ावा देगा।

उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ ही, 20,924 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं और 85,684 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। पिछले वर्ष 2025–2026 में, दिसंबर 2025 तक, औसत बिजली आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 49 मिनट और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे रही है।

वर्तमान वित्त वर्ष 2026–27 में ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए ₹65,926 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है।

ऊर्जा सेक्टर में विद्युत् वितरण क्षमता अर्थात सभी प्रकार –कमर्शियल, घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति, विद्युत वितरण क्षमता के सशक्त किये बिना यह संभव नहीं था। गत 9 वर्षों में यह क्षमता 17,000 मेगावाट से बढ़ कर आज 32,000 मेगावाट से अधिक है और इसके विस्तार की योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 2030 तक बिजली की मांग 50,000 मेगावाट होने का अनुमान है और इस मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन साथ वितरण क्षमता को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। ◆

मो. : 9935097419

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

समावेशी विकास, डिजिटल सुशासन

–अक्षत कोहली

'अंत्योदय' के महान आदर्श को आत्मसात करते हुए, राज्य सरकार ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने और वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता, बेटियों के लिए सुरक्षात्मक निवेश और शिक्षा के समान अवसरों ने एक ऐसे समाज की नींव रखी है जो न केवल समावेशी है, बल्कि भविष्योन्मुखी भी है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक पैमाना उसकी आर्थिक विकास दर की ऊँची मीनारें नहीं, बल्कि उसके समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की मुस्कान होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित 'सामाजिक न्याय' के संकल्प को धरातल पर उतारने का दायित्व राज्यों के कंधों पर है। इस संदर्भ में, उत्तर प्रदेश ने अपनी विशाल भौगोलिक सीमाओं और जनसांख्यिकीय जटिलताओं के बीच समाज कल्याण के जिस प्रतिमान को गढ़ा है, वह 'लोकतांत्रिक शासन' के संवेदनशील स्वरूप का जीवंत प्रमाण है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण सेक्टर महज 'वित्तीय सहायता' के पारंपरिक खांचे से बाहर निकलकर 'सशक्तीकरण और मानवीय गरिमा' के एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। यह बदलाव केवल नीतियों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन की उस कार्य–संस्कृति का परिचायक है, जहाँ तकनीक की शक्ति को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की पात्रता के साथ जोड़ा गया है। 'अंत्योदय' के महान आदर्श को आत्मसात करते हुए, राज्य सरकार ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने और वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता, बेटियों के लिए सुरक्षात्मक निवेश और शिक्षा के समान अवसरों ने एक ऐसे समाज की नींव रखी है जो न केवल समावेशी है, बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। आज उत्तर प्रदेश की यह सफलता की कहानी भारत के सहकारी संघवाद और जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दे रही है। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, दिव्यांगजन कल्याण, छात्रवृत्ति, सामूहिक विवाह एवं डिजिटल सुशासन जैसी बहुआयामी योजनाओं ने उत्तर

प्रदेश में समावेशी विकास की एक नई धारा प्रवाहित की है। इन योजनाओं का प्रभाव केवल प्रशासनिक आंकड़ों तक सीमित न रहकर सीधे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांगजन के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों ने असहाय वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों ने न केवल महिलाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ाई है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता की ओर भी अग्रसर किया है। सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं ने आर्थिक बोझ को कम करते हुए सामाजिक समरसता और समानता की भावना को मजबूत किया है। डिजिटल सुशासन ने पारदर्शिता, त्वरित सेवा वितरण और भ्रष्टाचार में कमी लाकर शासन प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनाया है। इन सभी प्रयासों के समन्वित परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हुआ है कि जब नीति, नीयत और निष्पादन एक ही दिशा में संगठित होकर कार्य करते हैं, तब विकास केवल एक नारा नहीं रहता, बल्कि वास्तविकता बनकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक भी प्रकाश की तरह पहुँचता है और उनके जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन स्थापित करता है।

समाज कल्याण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपलब्धियों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक एवं सुदृढ़ विस्तार प्रमुख रूप से सामने आता है। राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन तथा दिव्यांगजन पेंशन जैसी योजनाओं को न केवल व्यापक स्तर पर लागू किया है, बल्कि उन्हें अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी भी बनाया है। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के उन वर्गों को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है, जो परंपरागत रूप से सबसे अधिक असुरक्षित, उपेक्षित और निर्भर माने जाते रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत लाखों पात्र लाभार्थियों को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनके दैनिक जीवन में स्थिरता आई है और उनके जीवन स्तर में क्रमिक सुधार देखा गया है। यह आर्थिक सहायता केवल जीविका का साधन नहीं रही, बल्कि इसने उनके भीतर आत्मसम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की भावना को भी मजबूत किया है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों में इन योजनाओं का प्रभाव अधिक गहरा और परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली ने इस पूरी व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की है। पेंशन राशि का सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरण होने से

बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस डिजिटल व्यवस्था ने न केवल भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक सरल, तेज और विश्वसनीय बनाया है। परिणामस्वरूप यह स्पष्ट होता है कि यह प्रणाली केवल वित्तीय सहायता वितरण का माध्यम नहीं है, बल्कि सुशासन और सामाजिक न्याय की एक सशक्त आधारशिला के रूप में विकसित हुई है।

बाराबंकी जिले की 70 वर्षीय रामदुलारी देवी का अनुभव इस परिवर्तन की जीवंत और संवेदनशील अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। वे भावुक स्वर में बताती हैं कि पहले वृद्धावस्था में जीवन–यापन अत्यंत कठिन हो गया था और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी एक चुनौती बन गई थी, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमित लाभ ने उनके जीवन में स्थिरता और राहत का संचार किया है। अब इस सहायता से वे अपनी दवाइयों और आवश्यक खर्चों को सहजता से पूरा कर पाती हैं, जिससे उनके जीवन में न केवल आर्थिक सहारा मिला है, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के रामनरेश वर्मा का अनुभव भी इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वे बताते हैं कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है, जिससे किसी भी प्रकार की मध्यस्थता या असुविधा की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस पारदर्शी प्रणाली ने उन्हें न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि सामाजिक निर्भरता की भावना को भी समाप्त कर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की नई अनुभूति दी है। ऐसे असंख्य लाभार्थियों के अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि सामाजिक कल्याण योजनाएं केवल सरकारी सहायता कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि वे वास्तविक जीवन में गरिमा, सुरक्षा

और आत्मनिर्भरता स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाया है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने समाज कल्याण को सशक्त आधार प्रदान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं ने आर्थिक बाधाओं को दूर कर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। इन योजनाओं ने न केवल शैक्षिक अवसरों को विस्तारित किया है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा दिया है। छात्रावास, कोचिंग योजनाएं और तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता ने वंचित वर्गों के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। झाँसी की नेहा गौतम, जो एक छात्रवृत्ति लाभार्थी हैं, बताती हैं, "यदि छात्रवृत्ति न मिलती तो मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती। आज मैं स्नातक की पढ़ाई कर रही हूँ और भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। यह सहायता मेरे सपनों को साकार करने का माध्यम बनी है।" उनका अनुभव इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा में निवेश सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन है।

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी है। महिलाओं के लिए सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने, आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक पहलें की गई हैं। इन प्रयासों ने महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास और स्वाभिमान का संचार किया है। लखनऊ की पूजा सिंह कहती हैं, "आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों ने मुझे आत्मविश्वासी बनाया है। अब मैं स्वयं को अधिक सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हूँ।" यह अनुभव दर्शाता है कि समाज कल्याण केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना और मानसिक सशक्तीकरण का भी माध्यम है।

गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने सामाजिक समरसता को सुदृढ़ किया है। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत प्रदान करते हुए दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कानपुर के शबाना और इरफान बताते हैं, "हमारा विवाह इस योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ। इससे हमारे परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ा और हमें सम्मानपूर्वक जीवन की शुरुआत करने का अवसर मिला।" यह योजना सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हुई है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण भी उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण नीति का महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को पेंशन, सहायक उपकरण, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इससे वे आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। गोरखपुर के सुरेश कुमार, जिन्हें ट्राइसाइकिल और पेंशन

की सुविधा प्राप्त हुई है, कहते हैं, "अब मैं स्वयं अपने कार्य कर सकता हूँ। सरकार की सहायता ने मेरे जीवन को नई दिशा दी है।" यह परिवर्तन समाज में समान अवसर और संवेदनशीलता की भावना को सुदृढ़ करता है।

उत्तर प्रदेश ने समाज कल्याण के क्षेत्र में डिजिटल सुशासन को अपनाकर पारदर्शिता और दक्षता का नया अध्याय लिखा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार–आधारित सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और डिजिटल पोर्टल ने सेवा वितरण को सरल और प्रभावी बनाया है। इससे योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार हुआ है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई हैं। यह सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने राज्य को आधुनिक और उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में अग्रसर किया है। समाज कल्याण की इन पहलों ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए संचालित योजनाएं सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करती हैं। ये प्रयास भारतीय संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार करते हैं। राज्य ने यह सिद्ध किया है कि समावेशी विकास तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। इन योजनाओं का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी परिलक्षित होता है। गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, असमानताओं में कमी और सामाजिक सुरक्षा जैसे लक्ष्यों की दिशा में उत्तर प्रदेश की पहलें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह दर्शाता है कि राज्य का समाज कल्याण मॉडल राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक मानकों के अनुरूप भी विकसित हो रहा है। हालाँकि, इतनी व्यापक प्रगति के बावजूद कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव और लाभार्थियों की पहचान से जुड़ी जटिलताएं समय–समय पर सामने आती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जनजागरूकता अभियान, डिजिटल प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं। सरकार द्वारा इन मुद्दों पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे समाज कल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता और अधिक बढ़े।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं ने आर्थिक बाधाओं को दूर कर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। इन योजनाओं ने न केवल शैक्षिक अवसरों को विस्तारित किया है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा दिया है। छात्रावास, कोचिंग योजनाएं और तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता ने वंचित वर्गों के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है।

उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण मॉडल यह स्पष्ट करता है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि मानवीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। यह मॉडल सहायता से सशक्तीकरण, परोपकार से अधिकार और कल्याण से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर अग्रसर है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रतिबद्धता ने राज्य को 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के आदर्श को साकार करने में सक्षम बनाया है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण सेक्टर की सफलता करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की जीवंत कहानी है। यह कहानी उस बुजुर्ग के सम्मान की है जिसे पेंशन ने संबल दिया, उस छात्र के सपनों की है जिसे छात्रवृत्ति ने पंख दिए, उस बेटी की है जिसका विवाह गरिमा के साथ संपन्न हुआ, उस महिला की है जिसने आत्मविश्वास प्राप्त किया और उस दिव्यांगजन की है जिसने आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाया। यह कहानी संवेदनशील शासन, सुदृढ़ नीतियों और जनकल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की प्रेरक गाथा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण मॉडल निरंतर नवाचार और नीति–आधारित सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य

सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा विश्लेषण, लाभार्थी सत्यापन प्रणाली और एकीकृत डिजिटल डैशबोर्ड जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है। इससे न केवल लाभार्थियों की पहचान अधिक सटीक हुई है, बल्कि अपात्र लाभों की रोकथाम भी सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही, "वन स्टेट–वन पोर्टल" जैसी अवधारणाओं ने सेवाओं को और अधिक सरल एवं केंद्रीकृत बनाकर प्रशासनिक जटिलताओं को कम किया है। यह स्पष्ट संकेत है कि उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक कल्याणकारी मॉडल से आगे बढ़कर डेटा–संचालित शासन की ओर अग्रसर है।

भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण ढांचा "समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम" के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। आगामी वर्षों में ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, महिला डिजिटल उद्यमिता और युवा कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया जा सके। साथ ही, योजनाओं के सतत मूल्यांकन और सामुदायिक भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाकर शासन को अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सकता है। यदि यह गति और दृष्टि बनी रहती है, तो उत्तर प्रदेश न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक आदर्श समाज कल्याण मॉडल के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान और अधिक मजबूत करेगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण की यह यात्रा केवल योजनाओं के विस्तार की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक सशक्त और सतत गाथा है। यह यात्रा उस विचार को साकार करती है जिसमें विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार है। 2017 से 2025 की अवधि इस परिवर्तन का निर्णायक कालखंड रही है, जिसमें राज्य ने कल्याणकारी शासन से आगे बढ़कर अधिकार–आधारित, पारदर्शी और डिजिटल सुशासन की ओर महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। डीबीटी प्रणाली, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आधार–आधारित सत्यापन और ऑनलाइन सेवा वितरण ने योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है। वृद्धजन, दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाएँ, छात्र एवं वंचित वर्ग, सभी के जीवन में इन नीतियों ने स्थिरता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का संचार किया है। उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण मॉडल "वेलफेयर टू वेलबीइंग" की दिशा में एक परिवर्तनकारी एवं सतत विकासोन्मुख यात्रा का प्रतीक है, जो भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने हेतु एक मजबूत और स्थायी आधार प्रदान करता है। ◆

मो. : 9455926926

(लेखक आईटी इंजीनियर हैं)

सुमंगला से संवरते सपने

–डॉ. शिवानी कटारा

उत्तर प्रदेश के सामाजिक और शैक्षिक परिदृश्य में बीते कुछ वर्षों में एक शांत लेकिन गहरा परिवर्तन देखने को मिला है। इस बदलाव की धड़कन गांव–गांव में सुनाई दे रही है– जहां कभी बेटियों की पढ़ाई को बोझ समझा जाता था, वहीं आज बेटियां परिवार की उम्मीद और भविष्य की दिशा बन रही हैं। इस परिवर्तन के केंद्र में है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसने हजारों परिवारों की सोच और परिस्थितियों को बदलने का काम किया है। इसी परिवर्तन की एक जीवंत मिसाल है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रदौली रदौली, जिला कन्नौज की रहने वाली 19 वर्षीया नेहा की कहानी–एक ऐसी कहानी, जो संघर्ष से शुरू होकर आत्मविश्वास और उपलब्धि तक पहुंचती है।

एक साधारण मजदूर परिवार में जन्मी नेहा के लिए बचपन से ही जीवन आसान नहीं था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां खेतों में काम करके घर चलाने में हाथ बंटाती थीं। सीमित आय, बढ़ती जिम्मेदारियां और समाज की परंपरागत सोच–इन सबके बीच नेहा का बचपन बीता, जहां लड़कियों की पढ़ाई अक्सर प्राथमिक कक्षाओं के बाद थम जाती थी। लेकिन नेहा की किस्मत ने एक अलग रास्ता चुना। उसके जन्म के समय ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सलाह पर उसका पंजीकरण मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कर दिया गया। उस समय यह एक साधारण औपचारिकता लगी, लेकिन धीरे–धीरे यही निर्णय उसकी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव बन गया। योजना के तहत मिलने वाली छोटी–छोटी आर्थिक सहायता उसके जीवन में ऐसे समय पर आई, जब हर कदम पर रुकने की आशंका थी। जन्म के समय मिली राशि ने परिवार को बेटी के जन्म के प्रति एक नई संवेदना दी, तो टीकाकरण और शुरुआती पढ़ाई के दौरान मिली सहायता ने यह सुनिश्चित किया कि नेहा स्कूल तक पहुंच सके।

जब उसने कक्षा एक में प्रवेश लिया, तो पहली बार उसके हाथों में नई किताबें और स्कूल की यूनिफॉर्म आईं। यह सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि उसके सपनों का पहला आकार था। कक्षा छह और नौ तक

पहुंचते–पहुंचते, हर बार मिलने वाली सहायता ने एक अदृश्य सहारा बनकर उसकी पढ़ाई को जारी रखा। धीरे–धीरे उसके परिवार की सोच भी बदलने लगी। जहां कभी यह सवाल उठता था कि "लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करना है", वहीं अब यह विश्वास बनने लगा कि पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदल सकती है।

नेहा पढ़ाई में तेज थी। उसने 10वीं और फिर 12वीं अच्छे अंकों से पास की, लेकिन यहीं आकर उसकी राह सबसे कठिन हो गई। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक बार फिर वही पुराना सवाल सामने खड़ा था–क्या अब पढ़ाई यहीं रुक जाएगी? शादी की बातें होने लगीं और नेहा के सपने जैसे ठहरने लगे।

उसी समय योजना की अंतिम किस्त उसके खाते में आई। यह राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन गई। इसी मदद से उसने पास के कॉलेज में स्नातक में दाखिला लिया। उस दिन नेहा ने सिर्फ कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया, बल्कि अपनी जिंदगी के नए अध्याय में कदम रखा। नेहा कहती है, "अगर उस समय मदद नहीं मिलती, तो मेरी पढ़ाई यहीं खत्म हो जाती। आज मैं जो भी हूं, उसमें इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है।"

आज नेहा कॉलेज की छात्रा है। सुबह घर के काम, दिन में पढ़ाई और शाम को गांव की छोटी बच्चियों को पढ़ाना–यह उसकी नई दिनचर्या है। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों के लिए पढ़ रही है, जो कभी अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती थीं। उसकी मां की आंखों में अब चिंता नहीं, गर्व झलकता है। वह कहती हैं, "पहले लगता था बेटी बोझ है, अब वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।" नेहा की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत संघर्ष और सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन का संकेत भी है।

वर्ष 2024–25 से प्रभावी स्वरूप में संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा को एक मजबूत आधार दिया है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक छह चरणों में आर्थिक

पात्रता के अनुसार, लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। विशेष परिस्थितियों में, जैसे दूसरे प्रसव में जुड़वा बेटियां होने पर तीसरी बालिका को भी शामिल किया जाता है। योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलता है जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो। ये सभी प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और बेटियों के भविष्य को सशक्त बनाने में प्रभावी भूमिका निभाए।

सहायता प्रदान की जाती है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना में जन्म पर ₹5000, टीकाकरण के समय ₹2000, कक्षा एक में ₹3000, कक्षा छह में ₹3000, कक्षा नौ में ₹5000 और स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश पर ₹7000 की सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहती है। अब तक 27 लाख से अधिक बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं और सैकड़ों करोड़ रुपये सीधे उनके भविष्य में निवेश किए जा चुके हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित यह व्यवस्था आवेदन से लेकर भुगतान तक हर चरण को सरल और सुगम बनाती है। आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान है। इच्छुक अभिभावक आधिकारिक पोर्टल mksy.up.gov.in पर जाकर घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायता ले सकते हैं।

इस योजना का असर केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी है। नेहा के पिता, जो कभी पढ़ाई को लेकर संदेह में थे, अब गांव के अन्य लोगों को भी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक नया बदलाव देखने को मिला है– कई परिवारों ने अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने से रोका, बाल विवाह के मामलों में कमी आई, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और भ्रूण हत्याओं पर प्रहार हो रहा है। नेहा अब सिर्फ एक छात्रा नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल बन चुकी है–कि अब कोई भी बेटी केवल परिस्थितियों की वजह से पीछे नहीं रह जाएगी।

यह कहानी किसी एक की नहीं, बल्कि उन लाखों बेटियों की है, जिनकी जिंदगी में सही समय पर मिला एक छोटा सा सहारा एक बड़ी उड़ान में बदल गया। दरअसल, यह उस बड़े परिवर्तन का हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज एक सरकारी योजना से बढ़कर एक भावना बन चुकी है जहां बेटियां अब बोझ नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे मजबूत नींव हैं। और शायद यही इस बदलाव का सबसे सशक्त संदेश है–जब एक बेटी आगे बढ़ती है, तो उसके साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है। यह दिखाती है कि जब नीति और नीयत दोनों सही दिशा में हों, तो बदलाव अवश्य आता है। ◆

मो. : 9205269749

(लेखिका–दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनामिक्स से पीएचडी है एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय है)

नवाचार और विकास का संगम बनता यूपी

–डॉ. सुषमा गुप्ता

किसी प्रदेश की असली पहचान उसकी सड़कों, इमारतों या निवेश के आँकड़ों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में छिपी होती है जो वह अपने नागरिकों और निवेशकों के मन में जगाता है।भारत के विस्तृत मानचित्र पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा भू–भाग है, जो केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक विराट आख्यान है। यहाँ जनसंख्या आँकड़ों में सीमित नहीं रहती, वह आकांक्षाओं का अथाह सागर बन जाती है, जिसमें हर लहर अपने हिस्से के उजाले की तलाश में उठती है।

यह वही प्रदेश है, जहाँ इतिहास की परतें गहरी हैं और वर्तमान की चुनौतियाँ जटिल। यहाँ गाँवों की माटी में परंपरा की गंध है, तो शहरों की सड़कों पर बदलते समय की आहट। फिर भी, लंबे समय तक यह प्रदेश एक ऐसे द्वंद्व में उलझा रहा, जहाँ संभावना एक स्थायी वादा थी, लेकिन परिणाम एक अनिश्चित प्रतीक्षा रहे।

विकास यहाँ योजनाओं में तो था, पर जमीन पर उसका स्वर धीमा था। प्रशासनिक जटिलताएं, औद्योगिक ठहराव और कानून–व्यवस्था की उलझनें, इन सबने मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित किया, जहाँ प्रगति की गति बार–बार थम जाती थी। 2017 के बाद, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस कथा ने एक नया मोड़ लिया। यह परिवर्तन केवल नीतियों का नहीं, बल्कि शासन की शैली और दृष्टि का था। जहाँ विकास को घोषणा से निकालकर क्रियान्वयन के धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया।

उत्तर प्रदेश का अतीत हमें यह सिखाता है कि विकास केवल संसाधनों का खेल नहीं होता, यह संरचनाओं, नीतियों और विश्वास के ताने–बाने से निर्मित होता है। कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था ने इस प्रदेश को स्थिरता और जीवन का आधार दिया था। खेतों की हरियाली, ऋतुओं का चक्र और ग्रामीण जीवन की सहजता ने इसकी आत्मा को आकार दिया। परंतु समय के साथ यही आधार एक सीमा भी बन गया। औद्योगिक विविधता, तकनीकी नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ती दुनिया में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक ढाँचे में ही सिमटा रह गया।

निवेशक के लिए यह प्रदेश किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं था। यहाँ प्रवेश करने का अर्थ था, फाइलों की

अंतहीन यात्रा में उतरना। हर अनुमति एक नई प्रक्रिया, हर प्रक्रिया एक नया विभाग, और हर विभाग एक नई प्रतीक्षा। यह केवल प्रशासनिक जटिलता नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक थकान भी थी, जो धीरे–धीरे उत्साह को संदेह में बदल देती थी।

बुनियादी ढाँचा इस जटिलता को और गहरा कर देता था। असमान सड़कों पर चलती विकास की गाड़ी बार–बार धीमी पड़ जाती, बिजली की अनिश्चितता उत्पादन की लय को तोड़ देती, और औद्योगिक कॉरिडोर की कमी संभावनाओं को सीमित कर देती। यह सब मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करते थे, जहाँ आगे बढ़ने की इच्छा तो थी, पर रास्ते स्पष्ट नहीं थे। परंतु इन सबके ऊपर जो सबसे गहरी छाया थी, वह कानून–व्यवस्था की थी। यह छाया केवल घटनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक व्यापक धारणा के रूप में समाज में व्याप्त थी। "गुंडाराज" शब्द समय के साथ एक राजनीतिक आरोप से आगे बढ़कर एक सामाजिक मनोविज्ञान बन गया। एक ऐसा मनोविज्ञान, जिसने विश्वास की नींव को भीतर ही भीतर कमजोर कर दिया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वह रही कानून–व्यवस्था, भय से विश्वास तक की यात्रा।

निवेशक के लिए यह प्रदेश किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं था। यहाँ प्रवेश करने का अर्थ था, फाइलों की अंतहीन यात्रा में उतरना। हर अनुमति एक नई प्रक्रिया, हर प्रक्रिया एक नया विभाग, और हर विभाग एक नई प्रतीक्षा। यह केवल प्रशासनिक जटिलता नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक थकान भी थी, जो धीरे–धीरे उत्साह को संदेह में बदल देती थी।

हर विकास कथा का एक मौन, किंतु सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, सुरक्षा। बिना सुरक्षा के कोई भी आर्थिक गतिविधि स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकती, और बिना स्थायित्व के विकास केवल अस्थायी चमक बनकर रह जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था का प्रश्न लंबे समय तक केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय रहा है। यह वह क्षेत्र था, जहाँ सुधार के बिना किसी भी आर्थिक पहल की सफलता अधूरी रह जाती। इसी पृष्ठभूमि में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सख्त और स्पष्ट रुख सामने आया। संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई, अवैध संपत्तियों पर नियंत्रण और प्रशासनिक तंत्र की सक्रियता। इन सबने मिलकर एक नया संदेश दिया कि राज्य अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। यह बदलाव केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि धारणा में भी दिखाई देने लगा। निवेशकों के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण था कि अब जोखिम का स्तर घट रहा है और एक अधिक सुरक्षित वातावरण निर्मित हो रहा है।

व्यापार और उद्योग का संसार केवल पूँजी और संसाधनों पर नहीं टिकता। वह भरोसे पर खड़ा होता है। और जब यही भरोसा डगमगाने लगे, तो सबसे सशक्त संभावनाएँ भी सिमटने लगती हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यही वह निर्णायक बिंदु था, जहाँ विकास की कहानी बार–बार अधूरी रह जाती थी। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश का अतीत केवल पिछड़ेपन का आख्यान नहीं, बल्कि उन जटिल परिस्थितियों का दर्पण है, जिनमें विकास ने अपने कदम बार–बार रोके। यह वह पृष्ठभूमि है, जो वर्तमान परिवर्तन को समझने के लिए अनिवार्य है क्योंकि हर नई शुरुआत अपने भीतर बीते हुए समय की छाया भी समेटे रहती है।

हर युग अपने साथ एक नई भाषा लेकर आता है। ऐसी भाषा, जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सोच, दृष्टि और कार्यप्रणाली में परिवर्तन का संकेत देती है। शासन भी इससे अछूता नहीं रहता। दरअसल, शासन की असली पहचान उसकी नीतियों से उतनी नहीं बनती, जितनी उसकी कार्यशैली और नागरिकों के साथ उसके संवाद से बनती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह बदलाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है, जहाँ कभी प्रशासन एक जटिल तंत्र के रूप में देखा जाता था। फाइलों के ढेर, दफ्तरों के चक्कर और अनिश्चित प्रतीक्षा के साथ। निवेशक के लिए यह प्रक्रिया केवल औपचारिक नहीं, बल्कि मानसिक थकान का कारण भी बन जाती थी। लेकिन हाल के वर्षों में इस परिदृश्य में एक सूक्ष्म, किन्तु गहरा परिवर्तन

दिखाई देता है। यह परिवर्तन केवल नीतियों के स्तर पर नहीं, बल्कि शासन के "व्याकरण" में आया है। उस व्याकरण में, जो तय करता है कि राज्य अपने नागरिकों और निवेशकों से किस भाषा में संवाद करेगा।

"Ease of Doing Business" अब केवल एक आर्थिक शब्दावली नहीं रह गई है, बल्कि यह शासन की नई संवेदना का प्रतीक बन गई है। यह उस सोच को दर्शाती है, जहाँ सरकार स्वयं को एक नियंत्रक नहीं, बल्कि एक सहायक के रूप में देखने लगी है। इसी परिवर्तन का सबसे सशक्त उदाहरण "निवेश मित्र" जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। यह प्लेटफॉर्म केवल तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि प्रशासनिक दर्शन में बदलाव का प्रतीक है। जहाँ पहले निवेशक को अलग–अलग विभागों के द्वार खटखटाने पड़ते थे, वहीं अब एकीकृत प्रणाली के माध्यम से अनेक सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो गई हैं। यह बदलाव केवल सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि विश्वास की पुनर्स्थापना है। जब कोई प्रक्रिया समयबद्ध हो जाती है, तो वह केवल कार्य को तेज नहीं करती, बल्कि अनिश्चितता को भी समाप्त करती है। "अनुमति" अब एक अनंत प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक निश्चित समय–सीमा में पूरा होने वाला आश्वासन बनती जा रही है। शासन का नया व्याकरण रचा गया , पारदर्शिता और गति का उदय हुआ। स्व–प्रमाणन (self-certification) की व्यवस्था इस विश्वास को और गहरा करती है। यह उस मानसिकता का परिचायक है, जहाँ राज्य अपने नागरिक को संदेह की दृष्टि से नहीं, बल्कि जिम्मेदार सहभागी के रूप में देखता है। यह परिवर्तन सूक्ष्म अवश्य है, पर इसके दूरगामी प्रभाव हैं क्योंकि यह शासन और समाज के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित करता है।

इसी प्रकार, जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणाली (risk-based inspection) यह संकेत देती है कि अब निगरानी का उद्देश्य केवल नियंत्रण

इसी पृष्ठभूमि में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सख्त और स्पष्ट रुख सामने आया। संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई, अवैध संपत्तियों पर नियंत्रण और प्रशासनिक तंत्र की सक्रियता। इन सबने मिलकर एक नया संदेश दिया कि राज्य अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। यह बदलाव केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि धारणा में भी दिखाई देने लगा। निवेशकों के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण था कि अब जोखिम का स्तर घट रहा है और एक अधिक सुरक्षित वातावरण निर्मित हो रहा है।

प्रयास किया। यह आयोजन केवल औपचारिकताओं का उत्सव नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक उद्घोष था कि अब यह प्रदेश प्रतीक्षा की निष्क्रियता से बाहर निकलकर सहभागिता की सक्रियता की ओर बढ़ना चाहता है। वर्षों तक निवेश के लिए प्रतीक्षारत यह भूभाग अब स्वयं संवाद स्थापित करने की मुद्रा में था, जैसे वह कह रहा हो, "मैं तैयार हूँ, क्या आप हैं?"

नहीं, बल्कि दक्षता और पारदर्शिता है। हर इकाई को समान रूप से संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय, जोखिम के आधार पर प्राथमिकता तय करना एक अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सेवा वितरण की समयसीमा इस पूरे ढाँचे की आत्मा है। यह वह तत्व है, जो शासन को उत्तरदायी बनाता है। जब हर सेवा एक निश्चित समय के भीतर प्रदान करने का वादा करती है, तो यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक नैतिक अनुबंध बन जाता है, राज्य और नागरिक के बीच। इन सभी परिवर्तनों को यदि एक सूत्र में पिरोया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में शासन की भाषा बदल रही है।नियंत्रण से सहयोग की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, और सबसे महत्वपूर्ण, भय से विश्वास की ओर। यह परिवर्तन भले ही कागजों पर एक प्रशासनिक सुधार के रूप में दर्ज हो, पर वास्तव में यह एक गहरे सामाजिक–आर्थिक रूपांतरण की शुरुआत है। क्योंकि जब शासन अपने नागरिकों पर भरोसा करता है, तो नागरिक भी शासन पर भरोसा करने लगते हैं और यही विश्वास किसी भी विकास यात्रा की सबसे मजबूत नींव होता है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, जब राज्य केवल योजनाओं में नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास में दिखाई देने लगता है। UP Global Investors Summit ऐसा ही एक क्षण था। एक ऐसा मंच, जहाँ उत्तर प्रदेश ने स्वयं को नए रूप में प्रस्तुत करने का

जब टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप और हीरानंदानी ग्रुप जैसे बड़े औद्योगिक समूह इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो यह केवल निवेश प्रस्तावों का आदान–प्रदान नहीं होता, यह उस विश्वास का संकेत होता है, जो धीरे–धीरे राज्य की नई छवि के साथ जुड़ने लगता है। यह विश्वास आकस्मिक नहीं होता। यह नीतिगत सुधारों, प्रशासनिक बदलावों और कानून–व्यवस्था में आई स्थिरता का परिणाम होता है। निवेशक जब किसी राज्य की ओर देखते हैं, तो वे केवल लाभ की संभावनाएँ नहीं, बल्कि जोखिम की सीमाएँ भी तौलते हैं। इस दृष्टि से, यह मंच उत्तर प्रदेश के लिए एक "perception shift" का अवसर था, जहाँ वह अपने अतीत की छवियों से आगे बढ़कर एक नए भविष्य की संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा था।

परंतु हर चमक के पीछे एक प्रश्न भी छिपा होता है। एक ऐसा प्रश्न, जो किसी भी विकास कथा की वास्तविकता को परखता है। क्या ये समझौते, ये MoUs, कागजों की सीमाओं से बाहर निकलकर धरातल पर आकार ले पाएँगे? यही वह बिंदु है, जहाँ 'कार्यान्वयन अंतराल' की अवधारणा सामने आती है। यह वह महीन दरार है, जिसमें कई बार सबसे बड़ी घोषणाएँ भी चुपचाप खो जाती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि निवेश सम्मेलनों में किए गए वादे अक्सर अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए,

उत्तर प्रदेश के लिए असली चुनौती इस मंच की सफलता में नहीं, बल्कि उसके बाद की प्रक्रिया में निहित है। उस निरंतरता में, जहाँ हर प्रस्ताव को परियोजना में और हर परियोजना को वास्तविक उत्पादन में बदला जा सके।

यदि यह रूपांतरण सफल होता है, तो यह केवल निवेश का विस्तार नहीं होगा, बल्कि एक नए आर्थिक आत्मविश्वास की स्थापना होगी, जहाँ राज्य केवल अवसर प्रदान नहीं करेगा, बल्कि उन अवसरों को साकार करने की क्षमता भी प्रदर्शित करेगा। मिट्टी की महक से वैश्विक बाजार तक जाता समय है यह। विकास की सबसे सुंदर कहानियाँ वही होती हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं। आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की "One District One Product" (ODOP) योजना भी ऐसी ही एक कहानी है। जहाँ आधुनिक अर्थव्यवस्था और पारंपरिक शिल्प एक–दूसरे से संवाद करते दिखाई देते हैं। यह योजना भी केवल आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्स्मरण का प्रयास है। भदोही के कालीनों में बुनी हुई महीन कलाकारी, वाराणसी की साड़ियों में झलकती शाश्वत सौंदर्य–बोध, और मुरादाबाद के पीतल में ढली हुई कारीगरी, ये सब केवल उत्पाद नहीं हैं। ये समय की उन परतों के साक्ष्य हैं, जिनमें पीढ़ियों का श्रम, संवेदना और कौशल समाहित है।

जब ये पारंपरिक उत्पाद Amazon और Flipkart जैसे वैश्विक मंचों तक पहुँचते हैं, तो यह केवल बाजार का विस्तार नहीं होता, यह एक सांस्कृतिक संवाद बन जाता है। जहाँ गाँव का कारीगर, अपने छोटे सी कार्यशाला से निकलकर वैश्विक उपभोक्ता से जुड़ता है। इस दृश्य का उल्लेख अपने आप में अत्यंत अर्थपूर्ण है क्योंकि यहाँ विकास का अर्थ केवल औद्योगिक उत्पादन नहीं, बल्कि परंपरा का संरक्षण और उसका पुनर्स्थापन भी है। यह उस समावेशी विकास की झलक देता है, जिसमें विकास का लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि छोटे कारीगरों और स्थानीय समुदायों तक भी पहुँचता है।

फिर भी, इस उजली तस्वीर के पीछे कुछ छायाएं भी हैं। संसाधनों की कमी, वित्तीय सहायता का अभाव, तकनीकी उन्नयन की सीमाएं और वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा। ये सभी चुनौतियाँ अभी भी कई कारीगरों के रास्ते में खड़ी हैं। कई बार ऐसा होता है कि उत्पाद तो उत्कृष्ट होता है, पर उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग या गुणवत्ता मानक वैश्विक अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते। ऐसे में, वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए, ODOP की वास्तविक सफलता केवल बाजार तक पहुँच बनाने में नहीं, बल्कि उस संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में है, जो कारीगर को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि एक सक्षम उद्यमी में बदल सके। यदि यह संतुलन स्थापित हो जाता है, तो ODOP केवल एक योजना नहीं रहेगा, वह उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाएगा, जहाँ हर जिला अपने भीतर एक विशिष्ट कहानी और एक वैश्विक संभावना समेटे होगा। यदि विकास को एक जीवित शरीर के रूप में कल्पना करें, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर उसकी धमनियाँ हैं। वे अदृश्य रास्ते, जिनसे ऊर्जा, संसाधन और अवसर पूरे तंत्र में प्रवाहित होते हैं। जब ये धमनियाँ सशक्त और सुव्यवस्थित होती हैं, तब विकास केवल एक अवधारणा नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत अनुभव

बन जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इन्फ्रास्ट्रक्चर का यह पुनर्निर्माण विशेष महत्व रखता है। लंबे समय तक यह प्रदेश दूरी और असमानता के द्वंद्व में उलझा रहा, जहाँ एक क्षेत्र की प्रगति दूसरे क्षेत्र की दूरी में खो जाती थी।

ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे जैसे प्रकल्प केवल सड़क निर्माण की परियोजनाएं नहीं हैं, वे उस नई सोच के प्रतीक हैं, जो भूगोल को भाग्य में बदलना चाहती है। ये एक्सप्रेसवे दूरियों को केवल किलोमीटर में नहीं मापते, बल्कि वे समय, अवसर और संभावनाओं के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करते हैं। जहाँ पहले किसी क्षेत्र की पहचान उसके "पिछड़ेपन" से होती थी, वहीं अब वही क्षेत्र नए निवेश, नए उद्योग और नई उम्मीदों के केंद्र बनने की ओर अग्रसर हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (Uttar Pradesh Defence Industrial Coridor) एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरता है। यह केवल औद्योगिक विकास की योजना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दृष्टि का विस्तार है, जहाँ उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च–प्रौद्योगिकी उद्योगों के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कॉरिडोर उस बदलाव का संकेत है, जहाँ राज्य पारंपरिक उद्योगों की सीमाओं से बाहर निकलकर उन्नत विनिर्माण और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। यह एक ऐसे भविष्य की झलक है, जहाँ उत्तर प्रदेश केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक शक्ति के रूप में उभरता है।

इस प्रकार, इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ केवल निर्माण नहीं, बल्कि परिवर्तन का माध्यम है। एक ऐसा माध्यम, जो भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर आर्थिक संभावनाओं को नए आयाम देता है। नई अर्थव्यवस्था के साथ डिजिटल युग की दस्तक भी इसे नई ऊँचाइयों तक ले जा रही है। समय की धारा जब करवट लेती है, तो उसके संकेत सबसे पहले उन स्थानों पर दिखाई देते हैं, जहाँ भविष्य अपनी पहली रेखाएं खींचता है। उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का उभार इसी परिवर्तन का प्रतीक है। यह उभार केवल शहरी विस्तार नहीं, बल्कि आर्थिक चेतना के एक नए अध्याय का प्रारंभ है। लंबे समय तक पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर रहने वाला यह प्रदेश अब उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जहाँ विकास की धुरी बदल रही है। जहाँ पूँजी से अधिक महत्व ज्ञान का है, और संसाधनों से अधिक शक्ति तकनीक में निहित है। डेटा सेंटरों की ऊँची इमारतें, IT हब की गतिशीलता और डिजिटल सेवाओं का तीव्र विस्तार, ये सब मिलकर उस भविष्य की आहट देते हैं, जहाँ अर्थव्यवस्था भौतिक सीमाओं से परे जाकर आभासी संसार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है।

यह "new age economy" केवल उत्पादन का स्वरूप नहीं बदलती, बल्कि श्रम और कौशल की परिभाषा को भी पुनर्निर्धारित करती है। अब विकास का केंद्र केवल कारखानों की चिमनियाँ नहीं, बल्कि सर्वरों की गूंज और कोड की पंक्तियाँ बनती जा रही हैं। हालाँकि विकास को यदि केवल आँकड़ों में मापा जाए, तो वह अधूरा रह जाता है। उसका वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है, जब वह मनुष्य के जीवन को स्पर्श करता है। उसकी रोजमर्रा की वास्तविकताओं को बदलता है। जब उद्योग स्थापित होते हैं, तो केवल उत्पादन नहीं बढ़ता।जीवन की संभावनाएँ भी विस्तृत होती हैं। नए रोजगार के अवसर जन्म लेते हैं, परिवारों की आय में स्थिरता आती है, और एक नया मध्यम वर्ग आकार लेने लगता है। यह मध्यम वर्ग केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का वाहक होता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन–स्तर के नए मानक स्थापित करता है। उत्तर प्रदेश में यह परिवर्तन धीरे–धीरे परिलक्षित हो रहा है। शहरों की रफ्तार तेज हो रही है, उपभोग क्षमता में वृद्धि हो रही है, और आकांक्षाएँ पहले से अधिक स्पष्ट और मुखर हो रही हैं। आगे की राह, संतुलन ही कुंजी है। आज उत्तर प्रदेश एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। यह वह क्षण है, जहाँ दिशा का चुनाव आने वाले दशकों की तस्वीर तय करेगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुई यह परिवर्तन यात्रा इस बात का संकेत देती है कि जब शासन की मंशा स्पष्ट हो, नीतियाँ संगठित हों और क्रियान्वयन में दृढ़ता हो, तो बदलाव केवल संभव नहीं, बल्कि दृष्टिगोचर भी होता है। ◆

मो. : 9899916431

(लेखिका एमएनसी में एमडी हैं)

‘स्पेशल-300’ कसेगी अपराधियों की नकेल

–प्रद्युम्न तिवारी

सूबे में सरकार बनने के तुरन्त बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने अपराध और अपराधियों के प्रति 'जीरो टालरेंस' की नीति को अमली जामा पहनाया। उसके बाद अपराधियों पर लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार के तेवरों को भांप अपराधी या तो स्वयं ही सलाखों के पीछे चले गये या फिर उन्होंने दूसरे प्रदेशों में जाकर शरण ले ली। जिन्होंने सरकार और व्यवस्था से टकराने की सोची वे मिट्टी में मिला दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम के लिए बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे में अपराधियों के बचके निकलने के सारे रास्ते बंद हो जायेंगे। योगी सरकार ने प्रदेश की पुलिसिंग को तकनीक और वैज्ञानिक जांच से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने 300 प्रशिक्षित 'क्राइम सीन एक्सपर्ट' तैयार किए हैं। इन्हें ''स्पेशल 300'' नाम दिया जा रहा है। इस तीसरे बैच के प्रशिक्षण में 105 क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए गए हैं। दो बैच इससे पहले तैयार किए जा चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न कमिश्नरेट और जिलों से आए पुलिसकर्मियों ने 42 दिन का विशेष 'क्राइम सीन मैनेजमेंट' प्रशिक्षण पूरा किया। इसमें उन्हें साइबर एवं फॉरेंसिक तकनीकों की आधुनिक ट्रेनिंग दी गई।

प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए यूपीएसआईएफएस में क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने तकनीकी बारीकियों से दो–चार करा रहे हैं। उनका मत है कि अपराधी घटनास्थल पर कहीं न कहीं साक्ष्य अवश्य छोड़ता है। प्रशिक्षित पुलिसकर्मी अब ऐसी गलतियों को रोकेंगे, जिनके कारण कई बार जांच कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को निर्देश दिया कि वे अपने–अपने जनपदों और यूनिट्स में जाकर वर्कशॉप आयोजित करें। अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित करें। इससे क्राइम सीन मैनेजमेंट की विशेषज्ञता पूरे पुलिस बल तक पहुंचे। इससे पूरे प्रदेश में फॉरेंसिक आधारित जांच तंत्र मजबूत होगा। पांच चरणों में 500 एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे। इस तीसरे बैच के प्रशिक्षण में 105 क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए गए हैं। अफसरों को केवल पारंपरिक क्राइम सीन प्रबंधन ही नहीं, बल्कि साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण, वैज्ञानिक सैंपलिंग, एविडेंस प्रिजर्वेशन और टेक्नोलॉजी–आधारित जांच की बारीकियां भी सिखाई गईं।

दरअसल देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाने के बाद इनके तहत सात वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य किए गए हैं। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल दो फॉरेंसिक लैब थीं,

लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में विश्वस्तरीय स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन संचालित हो रहा है। इस संस्थान में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं।

इसके माध्यम से पुलिस कर्मियों के साथ–साथ उन युवाओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनकी रुचि फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में है। प्रत्येक जिले में ए–ग्रेड की छह फॉरेंसिक लैब निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा हर जिले में दो–दो मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी तैनात की गई हैं, जो घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संग्रह और जांच में मदद कर रही हैं। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए कई नई इकाइयों का गठन किया गया है। राज्य में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) का गठन किया गया है और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसके अलावा पहली बार पीएसी में महिला बटालियन का गठन किया गया है। अब तक तीन महिला बटालियन गठित की जा चुकी हैं और तीन नई बटालियनों के गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए कई नई इकाइयों का गठन किया गया है। राज्य में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) का गठन किया गया है और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसके अलावा पहली बार पीएसी में महिला बटालियन का गठन किया गया है। अब तक तीन महिला बटालियन गठित की जा चुकी हैं और तीन नई बटालियनों के गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

यह योगी सरकार की कार्यशैली ही थी कि पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था किसी चुनाव में मुद्दा बनी और इसी का परिणाम है कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सरकार बनायी। पुलिस विभाग ने वर्ष 2017 के बाद बिगड़े, अराजक, दंगाग्रस्त और कर्फ्यूग्रस्त राज्य को बदल करके सेफ यूपी के रूप में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने की शुरुआत कड़ी सुरक्षा से ही होती है। विकास की पहली शर्त सुरक्षा है। इसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबित किया है।

योगी सरकार ने यूपी का परसेप्शन चेंज करने के लिए कई कदम उठाए गए, तो कुछ रिफॉर्म किये गये। इसके नतीजे अब सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्ष 2017 में पीआरवी के वाहन 9,500 थे। आज इनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। वहीं वर्ष 2017 में टू व्हीलर मात्र 3,000 थे। आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यह केवल संख्या नहीं है, इसने पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त की है। आपातकालीन स्थिति में जितनी त्वरित कार्रवाई और सहायता पहुंचाएंगे, वही ट्रस्ट में

बदलती है। वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉडल पुलिसिंग के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी शामिल है। इसी आधार पर कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार मॉडल थानों और मॉडल फायर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पुलिस और आपदा सेवाओं को आधुनिक स्वरूप दिया जा सके।

पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता बहुत सीमित थी। एक साथ लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को ही प्रशिक्षण दिया जा सकता था। सरकार के सामने चुनौती थी कि लंबे समय से पुलिस भर्ती नहीं हुई थी और युवाओं में भर्ती को लेकर उत्सुकता थी, लेकिन प्रशिक्षण क्षमता सीमित होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कठिन था। किसी भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 9 महीने का समय लग जाता था। ऐसे में राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से संपर्क किया। दो–तीन राज्यों ने सहयोग के लिए सहमति दी। इसके अलावा सेना और अर्द्धसैनिक बलों से भी बातचीत की गई, जिन्होंने सहयोग देने की बात कही। इन सभी प्रयासों के बाद किसी तरह प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाकर लगभग 17 से 20 हजार तक पहुंचाया गया। इसके बाद अन्य राज्यों तथा सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की मदद से इसे करीब 30 हजार तक ले जाया गया, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है और इन सभी को उत्तर प्रदेश के अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में विकसित किए गए नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यह संभव हो पाया है।

मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक पुलिस व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास प्रारंभ किए गए। इन सभी को मिलाकर जब टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ काम करते हैं तो रिजल्ट आता है। यही कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार बनता है। आज देश और दुनिया के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। इसका प्रमुख कारण राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति है। इसके साथ ही प्रदेश में हर बेटी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षा का अनुभव करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही प्रदेश और देश के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। ◆

मो. : 9935097419

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

8 हजार बढ़े मानदेय और खिल उठे चेहरे

–डॉ. सुयश नारायण मिश्रा

किसी सरकारी आदेश की असली कीमत फाइलों में नहीं, घरों की रसोई में दिखाई देती है। कभी बच्चों की कॉपी–किताब में, कभी बूढ़े पिता की दवा में, कभी बेटी की अधूरी कोचिंग में, तो कभी उस स्त्री की आँखों में, जो हर महीने के आखिर में उधार मांगते हुए भीतर ही भीतर टूट जाती है। सरकारी घोषणाएं अक्सर खबर बनती हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ खबर नहीं रहते, वे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2026 से ऐसा ही एक फैसला हजारों परिवारों के जीवन में नई सांस बनकर उतरा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1.43 लाख से अधिक शिक्षामित्रों और लगभग 25 हजार अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी वृद्धि कर एक ऐसे ही लंबे इंतजार को राहत में बदल दिया है। शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 18 हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार ने इस निर्णय के लिए 250 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं और मई माह में पहली बार बढ़ा हुआ मानदेय सीधे उनके खातों में पहुंचेगा। कागज पर यह सिर्फ 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी लग सकती है, लेकिन उन परिवारों के लिए, जिन्होंने वर्षों तक हर महीने का बजट उधारी, कटौती और समझौतों के सहारे बनाया हो, यह सिर्फ रकम नहीं, राहत, सम्मान और एक नई उम्मीद है। यह फैसला इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी योगी सरकार ने वर्ष 2017–18 में भी शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया था। उस समय भी यह निर्णय हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत बना था। अब नौ वर्षों बाद यह दूसरी बड़ी वृद्धि है, जो यह संकेत देती है कि सरकार ने सिर्फ घोषणा नहीं की, बल्कि लगातार इस वर्ग की आर्थिक जरूरतों, सामाजिक सम्मान और व्यावहारिक कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया। सबसे

महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं विधानसभा सत्र के दौरान इसकी घोषणा की और मात्र एक महीने के भीतर कैबिनेट बैठक कर इसे पूरी तरह लागू भी कर दिया गया। अक्सर सरकारी घोषणाएं लंबी प्रक्रिया में अटक जाती हैं, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री ने स्वयं पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग की। यही कारण है कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मई माह में ही पहली बार बढ़ा हुआ भुगतान मिल जाएगा। यह सिर्फ प्रशासनिक तेजी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का भी संकेत है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षामित्र और अनुदेशक मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वे लगातार यह कहते रहे कि 10 हजार या 9 हजार रुपये में परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई कराना, इलाज करवाना और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना लगभग असंभव होता जा रहा है।

महंगाई के इस दौर में उनका संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी था। कई शिक्षामित्र ऐसे हैं जो परिवार से दूर तैनात हैं, किराया अलग देते हैं, बच्चों की फीस अलग भरते हैं और फिर भी महीने के अंत तक हाथ खाली रह जाते हैं। कम मानदेय की वजह से कई बार उन्हें अपनी जरूरतों से पहले बच्चों की जरूरतें चुननी पड़ती थीं। किसी ने बेटी की कोचिंग टाल दी, किसी ने पिता की दवा उधार में खरीदी, किसी ने अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ घर चलाने को प्राथमिकता दी। ऐसे में यह बढ़ोतरी सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि वर्षों के धैर्य और संघर्ष की एक स्वीकारोक्ति है। जब हमने कई शिक्षामित्रों और अनुदेशकों से बात की, तो उनकी प्रतिक्रियाओं में एक बात समान थी, राहत के साथ सम्मान की अनुभूति। किसी ने कहा कि अब बच्चों की पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सकेगी, किसी ने कहा कि अब उधारी कम होगी, तो किसी ने इसे "सम्मान की वापसी" बताया। कई महिला शिक्षामित्रों ने कहा कि अब परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाना पहले से आसान होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1.43 लाख से अधिक शिक्षामित्रों और लगभग 25 हजार अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी वृद्धि कर एक ऐसे ही लंबे इंतजार को राहत में बदल दिया है। शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 18 हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार ने इस निर्णय के लिए 250 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं और मई माह में पहली बार बढ़ा हुआ मानदेय सीधे उनके खातों में पहुंचेगा।

सीतापुर के लहरपुर ब्लॉक में कार्यरत शिक्षामित्र उपमा शुक्ला की आँखें उस समय भर आईं, जब उनसे पूछा गया कि मानदेय में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी से उनके जीवन में क्या बदलेगा। कुछ क्षण तक वह चुप रहीं, फिर धीमी आवाज़ में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी, जिसमें संघर्ष है, दूरी है, जिम्मेदारियाँ हैं और अब एक नई उम्मीद भी। उपमा ने बताया कि उनका बेटा लहरपुर के ही एक स्कूल में पढ़ता है, जबकि उनके पति लखनऊ में नौकरी करते हैं। ससुराल और मायके के बीच करीब 125 किलोमीटर की दूरी ने उनके जीवन को दो हिस्सों में बाँट दिया है। परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि उन्हें परिवार से दूर रहकर मायके में ही गुज़ारा करना पड़ा। बेटे की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियाँ और नौकरी, सब कुछ अकेले संभालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वह कहती हैं कि मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा बेटा लखनऊ में अपने पिता के साथ रहकर अच्छी पढ़ाई करे। वह अभी सिर्फ 6 साल का है और पिछले दो साल से मेरे साथ रहकर ही पढ़ रहा है। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मैं उसे लखनऊ के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला पा रही थी। कई बार मन बहुत भारी हो जाता था, क्योंकि एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य चाहती थी, लेकिन सीमित आय रास्ता रोक देती थी। उपमा के लिए यह सिर्फ आर्थिक परेशानी नहीं थी, बल्कि भावनात्मक संघर्ष भी था। पति लखनऊ में, बेटा उनके साथ, और खुद दो शहरों के बीच बँटी ज़िंदगी, हर दिन एक नई चुनौती। परिवार साथ होते हुए भी साथ नहीं था। अब योगी सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी और महिला शिक्षामित्रों को पति के कार्यस्थल के पास तबादले की सुविधा ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगा दी है।

खुद मॉनिटरिंग नहीं की होती, तो शायद यह फैसला इतनी जल्दी लागू नहीं हो पाता। हम सभी शिक्षामित्र उनकी इस संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

सरोजनीनगर के रामदासपुर में तैनात शिक्षामित्र संतोष कुमारी अवस्थी के चेहरे पर संतोष भी है और उम्मीद भी। मानदेय बढ़ने की खबर ने उन्हें राहत दी है, लेकिन वे मानती हैं कि अभी और सैलरी बढ़नी चाहिए। वह कहती हैं कि पैसे बढ़े जरूर हैं, इससे खुशी है और राहत भी मिली है। लंबे समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे। महंगाई के इस दौर में 18 हजार रुपये बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी इससे स्थिति जरूर बदलेगी। अगर यह 25 हजार तक हो जाता तो और बेहतर होता, लेकिन फिलहाल यह फैसला भी संतोषजनक है। दो बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कम मानदेय में घर चलाना आसान नहीं था। वह बताती हैं, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बीकॉम कर रहे हैं। 10 हजार रुपये में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था। कई बार जरूरी चीजों को टालना पड़ता था। अब बढ़े हुए मानदेय से उन्हें उम्मीद है कि बच्चों की पढ़ाई में पहले जैसी दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों के लिए और बेहतर किया जा सकेगा। उनकी पढ़ाई, जरूरतें और भविष्य को लेकर थोड़ी राहत महसूस हो रही है। इससे हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा। संतोष कुमारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योगी जी ने दो बार हम लोगों का मानदेय बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। अगर उन्होंने

बच्चों की पढ़ाई आसान हो गई

राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र के सहजनपुर में जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षामित्र बृजेश कुमार चौधरी ने कहा कि मानदेय में आठ हजार रुपये की बढ़ोतरी से काफी राहत मिली है। अब बच्चों की फीस भरना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया, "मेरे दो बच्चे हैं। एक कक्षा 9 में पढ़ता है और दूसरा हाईस्कूल में है। सिर्फ उनकी फीस पर ही हर महीने 7 से 8 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यह बढ़ा हुआ मानदेय हमारे लिए बड़ी राहत है।" बृजेश ने कहा कि यदि मानदेय 30 हजार रुपये तक हो जाता तो और बेहतर होता, लेकिन फिलहाल यह बढ़ोतरी भी राहत भरी है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर दूसरी जगह नौकरी करना आसान नहीं है। उम्मीद लगाकर इतना समय निकल गया। अब सैलरी बढ़ी, अच्छा लगा है। उन्होंने बताया कि नौकरी आसान नहीं थी लेकिन गांव में रहते हैं, खेत भी है और स्कूल भी पास में है, इसलिए आने-जाने में एक भी रुपये का खर्च नहीं लगता। इससे कुछ सहारा मिल जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। उम्मीद है कि भविष्य में शिक्षामित्रों के लिए और भी बेहतर निर्णय लिए जाएंगे।

अब महीने के आखिरी में उधार नहीं मांगना पड़ेगा

लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में पिछले डेढ़ दशक से कार्यरत शिक्षामित्र नीतू सुबह पाँच बजे उठती हैं। घर का काम, बच्चों का टिफिन, स्कूल की तैयारी, फिर बस पकड़कर विद्यालय पहुँचना, यह उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी है। दूसरों के बच्चों को अक्षर सिखाने वाली नीतू अपने ही घर के बजट के सामने कई बार असहाय हो जाती

थीं। वह कहती हैं कि 10 हजार रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल था। बच्चों की फीस, राशन, किराया, बिजली, आने–जाने का खर्च, सब उसी में। अक्सर बजट बिगड़ ही जाता था। अब 18 हजार मिलेंगे तो कम से कम इतना तो लगेगा कि हमारी मेहनत की कीमत समझी गई है। पहली बार लग रहा है कि महीने के आखिरी में डर नहीं होगा। नीतू ने बताया कि वह एक नियमित शिक्षक की तरह चुनाव ड्यूटी, सर्वे, जनगणना, पोषण अभियान, सभी जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन वेतन और सम्मान दोनों कम थे। योगी सरकार ने कम से कम यह स्वीकार किया कि हम भी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह राहत है और राहत बहुत बड़ी चीज़ होती है।

नहीं रुकेगी बेटी की कोचिंग

सीतापुर के एक जूनियर हाईस्कूल में विज्ञान पढ़ाने वाले एक अनुदेशक ने नाम न छापने का वादा लेकर हमसे बात की। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक है। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को विज्ञान पढ़ाता हूं, लेकिन कई बार अपनी बेटी के ट्यूशन के लिए पैसे नहीं जुटा पाता हूं। कोचिंग फीस भरने के लिए कई बार दोस्तों से उधार लिया। एक बार तो बाइक गिरवी रखने की नौबत आ गई थी तब बेटी ने कहा, पापा, अगर पैसे की दिक्कत है तो मैं कोचिंग छोड़ देती हूं। उस दिन लगा जैसे मैं हार गया हूं। अब 17 हजार रुपये मिलने की खबर सुकून से कम नहीं है। हालांकि 17 हजार बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब बच्चों की पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी। कम से कम यह डर नहीं रहेगा कि फीस कैसे भरेंगे। सरकार ने हमारी भूमिका को स्वीकार किया। यह एहसास कि हम भी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। पैसा जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है।"

कई शिक्षामित्र ऐसे हैं जो परिवार से दूर तैनात हैं, किराया अलग देते हैं, बच्चों की फीस अलग भरते हैं और फिर भी महीने के अंत तक हाथ खाली रह जाते हैं। कम मानदेय की वजह से कई बार उन्हें अपनी जरूरतों से पहले बच्चों की जरूरतें चुननी पड़ती थीं। किसी ने बेटी की कोचिंग टाल दी, किसी ने पिता की दवा उधार में खरीदी, किसी ने अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ घर चलाने को प्राथमिकता दी। ऐसे में यह बढ़ोतरी सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि वर्षों के धैर्य और संघर्ष की एक स्वीकारोक्ति है। जब हमने कई शिक्षामित्रों और अनुदेशकों से बात की, तो उनकी प्रतिक्रियाओं में एक बात समान थी, राहत के साथ सम्मान की अनुभूति। किसी ने कहा कि अब बच्चों की पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सकेगी, किसी ने कहा कि अब उधारी कम होगी, तो किसी ने इसे "सम्मान की वापसी" बताया। कई महिला शिक्षामित्रों ने कहा कि अब परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाना पहले से आसान होगा।

मानदेय बढ़ने की खुशी और तबादले की उम्मीद

मानदेय बढ़ा है, खुशी है, लेकिन हजारों महिला शिक्षामित्रों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती अब भी वही है घर से बहुत दूर तैनाती। बाराबंकी में तैनात एक महिला शिक्षामित्र की शादी 2018 में रायबरेली से जिले में हो गई। अब वह अपने पति के घर नहीं जा पा रही हैं। ऐसे में उन्होंने योगी सरकार का आभार जताया कि सरकार ने उनके जैसी तमाम महिलाओं के लिए सोचा है। योगी सरकार महिला शिक्षामित्रों को उनके पति के घर के निकट भेजने जा रही है। अब पैसा बढ़ चुका है घर वापसी भी हो जाये तो जीवन सुधर जायेगा। वह बताती हैं कि यह सुरक्षा और गरिमा का सवाल है। पुरुषों के लिए दूरी अलग बात है, लेकिन महिलाओं के लिए यह रोज़ की जंग है। देर शाम लौटना, बच्चों की चिंता, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ साथ चलता है। योगी सरकार से उनकी सबसे बड़ी उम्मीद अब यही है मानदेय के बाद स्थानांतरण भी जल्द होगा। अगर सरकार यह भी कर दे, तो हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी।

नौ वर्षों में दूसरी वृद्धि

नौ वर्षों में दूसरी बड़ी वृद्धि सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर खड़े कर्मियों को भी देख रही है। कई शिक्षामित्र कहते हैं कि पहले उन्हें सिर्फ अस्थायी कर्मचारी की तरह देखा जाता था, लेकिन अब कम

से कम यह विश्वास बना है कि उनकी आवाज़ शासन तक पहुँचती है। यह भरोसा किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होता है। शिक्षामित्र संगठनों का कहना है कि यह फैसला लंबे संघर्ष और लगातार संवाद का परिणाम है। कई वर्षों से मानदेय वृद्धि की मांग चल रही थी। धरना, ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल, हर स्तर पर हमने अपनी बात रखी। सरकार ने आखिरकार सकारात्मक निर्णय लिया। इसका स्वागत होना चाहिए।

क्या कहा बहराइच जिले के शिक्षामित्रों ने

बहराइच जिले के शिक्षामित्र राजेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम सराहनीय है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देगी। मानदेय बढ़ने से काफी हद तक राहत मिलेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हूजूरपुर ब्लॉक के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश जायसवाल ने कहा कि सरकार की इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। अब हम अपने बच्चों को और बेहतर शिक्षा दे सकेंगे और अपने माता–पिता के इलाज व दवाइयों का खर्च भी आसानी से उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश प्रवक्ता एवं जिलाध्यक्ष बहराइच शिवश्याम मिश्र ने कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का शिक्षामित्रों की ओर से धन्यवाद। उन्होंने बताया कि शिक्षामित्रों के संघर्षकाल में अब तक पांच बार मानदेय बढ़ा है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में केवल तीन बार ही बढ़ोतरी हुई और वह भी सिर्फ सैकड़ों में। जबकि योगी सरकार ने दो बार मानदेय में बड़ी वृद्धि की पहली बार वर्ष 2017 में 3500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया और अब 2026 में 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सराहनीय है और इससे हमारी आर्थिक समस्याओं का काफी हद तक समाधान हुआ है। हालांकि, 'सेम वर्क, सेम सैलरी' की मांग अब भी बनी हुई है। शिक्षामित्रों ने बेसिक शिक्षा व्यवस्था को जीवन दिया है और अल्प मानदेय में वर्षों तक अपना जीवन गुजारा है। कई शिक्षामित्र रिटायर हो चुके हैं और कई रिटायरमेंट के करीब हैं। ऐसे में जिनकी नौकरी के केवल 10 से 15 वर्ष शेष हैं, उन्हें सरकार अतिरिक्त सुविधाएं देकर आगे बढ़ाएगी, ऐसी उम्मीद है। शिक्षामित्र प्रदीप अवस्थी ने कहा कि मानदेय वृद्धि से राहत जरूर मिली है, लेकिन अपेक्षा है कि आगे सरकार हमें स्थायी भी करेगी, ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। ◆

मो. : 8924856004

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

सशक्त नारी विकसित राज्य

–मुकुल मिश्रा

सशक्त नारी विकसित राष्ट्र की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार करने वाले योगी ने जबसे प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभाली है, उन्होंने युवतियों को सुरक्षित वातावरण का एहसास कराया है। किसी भी देश–प्रदेश की उन्नति तब संभव है जब महिलाओं को समान आर्थिक अवसर मिलें और निर्भीक रहकर वह समाज में योगदान कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि महिलाओं की सुरक्षा के बिना स्वावलंबन संभव नहीं। बेटी अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगानेवालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। महिलाओं ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट–वन कुजीन महिलाओं के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। यूपी में लगभग बीस हजार स्टार्टअप हैं, जिनमें आधे से अधिक महिलाओं द्वारा ही संचालित हैं। इसके साथ ही आठ हजार न्याय पंचायतों में डिजिटल इंटरप्रेन्योर योजना लागू की जा रही है, जिससे हजारों महिलाएं रोजगार व उद्यमिता से जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री के शब्दों में नारी सुरक्षित होगी तो समाज सुरक्षित होगा। नारी का सम्मान होगा तो समाज का सम्मान होगा। उन्होंने जल्द ही विभिन्न जिलों में पांच सौ क्षमतावाले वर्किंग विमेन हास्टल बनाए जाने की बात भी कही। योगी ने कहा कि इससे नौकरी करनेवाली बेटियों को सुरक्षित आवास मिलेंगे।

योगी सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराये हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक विकास का या फिर रोजगार का। सरकार ने इसके लिए अनेक योजनाएं बनायी हैं और उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाया। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों की फौज उतारी कि वे एयरकंडीशन कमरों से निकलकर जमीनी स्तर पर जाकर उन योजनाओं को परखें और अगर कहीं कोई कमी रह गयी हो तो उसे दूर करें। सरकार ने महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं समझा बल्कि उन्हें भावी भारत की तकदीर मानते हुए उनकी तस्वीर को बदलने में जुट गयी हैं।

योगी सरकार का मानना है कि जब तक इस आधी आबादी की हर क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी नहीं होगी, तब तक प्रदेश और देश का विकास संभव नहीं है। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चाहिए सुरक्षित माहौल और सुविधाएं, जिसके लिए योगी सरकार का हर विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। हर विभाग में महिलाओं के लिए पृथक योजनाएं बनायी गयीं और अलग से उन्हें सुविधाएं दी गयी हैं। जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ें। कहना गलत न होगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर केंद्रित नीतियों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का एक नया मॉडल पेश किया है। आम जनता को सुरक्षित वातावरण देने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्षम एवं सुदृढ बनाया गया है। उसी का नतीजा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में वर्ष 2016 के मुकाबदले हत्या में 48 प्रतिशत की कमी आयी। इसी तरह दहेज के मामलों में 19

प्रतिशत, मृत्यु दर में 67 प्रतिशत, बलात्कार और शीलभंग के मामलों में 34 प्रतिशत की कमी आयी है।

योगी आदित्यनाथ के इस बार वर्ष 2026–27 के बजट में महिलाओं–युवतियों के उत्थान व उनके कल्याण पर खासा जोर दिया है। महिला सशक्तीकरण को और मजबूत बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं। महिला और बाल विकास की योजनाओं के लिए 18620 करोड़ की व्यवस्था की गयी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक धनराशि की व्यवस्था की गयी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौकरी के साथ ही साथ रोजगार पर भी सरकार ने अपना फोकस बढ़ाया है और महिला उद्यमियों के लिए महिलाओं को सस्ती दर पर लोन देने की व्यवस्था की गयी। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए सौ करोड़ से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना शुरू होगी। बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन के लिए 3500 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। इस योजना में लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2016–17 में 17 लाख 32 लाख थी, जो बढकर 2025–26 में 38 लाखा 58 हजार 922 हो गयी है। सरकार ने चालीस फीसदी या इससे अधिक दिव्यांगता

योगी सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराये हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक विकास का या फिर रोजगार का। सरकार ने इसके लिए अनेक योजनाएं बनायी हैं और उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाया। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों की फौज उतारी कि वे एयरकंडीशन कमरों से निकलकर जमीनी स्तर पर जाकर उन योजनाओं को परखें और अगर कहीं कोई कमी रह गयी हो तो उसे दूर करें। सरकार ने महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं समझा बल्कि उन्हें भावी भारत की तकदीर मानते हुए उनकी तस्वीर को बदलने में जुट गयी है।

वाली छात्राओं को स्कूल जाने के लिए ई–ट्राइसाइकिल देने का ऐलान किया है। मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला बीट कर्मियों को क्षेत्र में आने–जाने के लिए वाहन खरीदने के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था इस बार बजट में की गयी है। जिन विकास खण्डों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए नई योजना के तहत 580 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के लिए बजट में चार सौ करोड़ का बजट भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए सभी वर्गों की बालिकाओं के विवाह के लिए अनुदान की राशि बढ़ायी गयी है, जो बढ़कर अब 1.01 लाख कर दी गयी है और इसके लिए इस बार बजट में 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले अनुदान योजना के लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए 50 करोड़ और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना के लिए 210 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी तरह महिला गन्ना किसानों को गन्ने की पर्ची जारी करने में प्राथमिकता दी जायेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की 60 हजार महिला गन्ना किसान लाभान्वित होंगी।

योगी सरकार ने सरकारी ही नहीं निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनायी है। पिछले माह आठ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल की गयी और पिंक रोजगार महाकुंभ–2026 का आयोजन हुआ। इस आयोजन में शिक्षित युवतियों और महिलाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों से सीधे जोडकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये। सरकार के इस प्रयास ने इसमें पांच हजार युवतियों और महिलाओं को रोजगार मुहैय्या करवाये। जिसमें 18 से 40 वर्ष की महिलाएं शामिल रहीं। हालांकि दसवीं, बारहवीं, स्नातक, परास्नातक, बी.टेक, बीबीए, एमबीए, फार्मेसी सहित अन्य तकनीकी और सामान्य डिग्रीधारी महिलाओं ने पहले से रोजगार संगम पोर्टल और नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आवेदन किया था।

योगी सरकार ने बालिकाओं को शिक्षा के अवसर मुहैय्या कराने के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की जिसमें जनवरी 2026 तक 26.71 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं। निर्धन परिवार की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलायी गयी, जिसमें पांच लाख 20 हजार से अधिक बेटियों का विवाह करवाया गया है। लखपति महिला योजना में 35 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया और 18.55 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। 39885 बी.सी. सखियों द्वारा कार्य करते हुए 42,711 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन–देन किया गया व 116 करोड़ का लाभांश अर्जित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में 9.43 लाख से अधिक समूहों, 64761 ग्राम संगठनों एवं 3296 संकुल स्तरीय संघों का गठन किया गया और 1.06 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की पेंशन में पांच गुना की बढ़ोत्तरी योगी सरकार ने की है। राज्य की 26.81 लाख निराश्रित महिलाओं को नियमित मासिक पेंशन 2017 में तीन सौ रूपये दी जाती थी, जिसे पहले बढ़ाकर एक हजार किया गया जो अब बढ़ाकर पन्द्रह सौ मासिक कर दी गयी है।

महिलाओं के लिए हर घर नल से जल योजना भी वरदान साबित हो रही है। पहले पानी लाने के लिए इनको घर से कोसों दूर पानी लेने जाना पड़ता था। उस दूरी को तय करने पर न सिर्फ कई घटनाएं हो जाती थीं बल्कि दिन का आधा समय इसी में व्यतीत हो जाता था। पहले परिवार के लिए पानी जुटाना हो या फिर भोजन बनाने के लिए लकड़ी एकत्रित करना, एक बड़ी समस्या के रूप में महिला को ही इससे रूबरू होना पड़ता था। अब नल से जल और गैस सिलेण्डर ने उन्हें काफी राहत दी है। इसी तरह स्थानीय रोजगार व महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला पर्यटक गाइडों को दस हजार लाइसेन्स शुल्क माफ कर दिया गया। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से हर जिले में एक महिला थाना बनाया गया।इसके अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष की तैनाती की गयी। 19839 महिला पुलिसकर्मियों को नियुक्त करते हुए 9172 महिला बीटों का आवंटन किया गया। जिससे कोई भी पीड़ित महिला अपनी बात आसानी से महिला पुलिस पुलिसकर्मियों के साथ साझा कर सके। प्रदेश की योगी सरकार जिस प्रतिबद्धता से राज्य की महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार कर रही है, उससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश महिलाओं व बेटियों के लिए सपनों की उड़ान भरनेवाला नंबर वन प्रदेश बन जायेगा। ◆

मो. : 9415464591
(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं)

‘बेसिक’ से ‘बेहतर’ की ओर बढ़ते कदम

—ऋचा सिंह

असली भारत गाँव में बसता है, और गाँव का भविष्य स्कूलों में गढ़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में 1.13 लाख परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें 1.9 करोड़ बच्चे कक्षा 1 से 8 तक पढ़ते हैं। पहले इन स्कूलों की पहचान जर्जर भवन, शिक्षक विहीन कक्षा और मिड–डे मील की अनियमितता थी। अब कुछ वर्षो से तस्वीर बदली है। ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ से ‘निपुण भारत’ तक, सरकार ने सुविधाओं का पूरा ईको–सिस्टम खड़ा किया है। जिसका सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। आज बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों की शैक्षिक व सांस्कृतिक प्रस्तुति नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का ही प्रतिफल है। आज विद्यालयों की चमचमाती फर्श, कक्षाओं की दीवारों पर लगे अत्याधुनिक डिजिटल बोर्ड, शिक्षकों के पास टैबलेट, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान किट, बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण और सुरक्षित चारदीवारी की उपलब्धता बच्चों और शिक्षकों के कला कौशल में झलक रही है।

भौतिक अवस्थापना सुविधाएं

ऑपरेशन कायाकल्प : 19 मूलभूत सुविधाएं

- वर्तमान में 96.3% स्कूलों में बालक–बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय, रनिंग वॉटर युक्त शौचालय क्रियाशील हैं। 2018 में यह 68: था। स्वच्छता का सीधा असर बालिका नामांकन पर पड़ा है। कक्षा 6 में बालिका नामांकन 2020 के 78% से बढ़कर 86: हो गया।
- **पेयजल** : 93% स्कूलों में सबमर्सिबल, इंडिया मार्का–2 या RO युक्त शुद्ध पेयजल। ‘जल जीवन मिशन’ से 62,000 स्कूलों को नल कनेक्शन मिला। जल जांच किट की हर ब्लॉक व विद्यालय पर उपलब्धता।

- **विद्युतीकरण** : 94.2% स्कूल ग्रिड से जुड़े। 18,200 स्कूलों में सोलर पैनल लगे हैं। बिजली कटौती में भी पंखा–लाइट चलती है। अब गर्मी–बरसात पढ़ाई की बाधक नहीं।
- **फर्नीचर** : 85.6% स्कूलों में कक्षा 1–5 के 100% बच्चों के लिए डेस्क–बेंच। 'टाट–पट्टी युग' खत्म अब बच्चे आत्मविश्वास के साथ कक्षाओं में बैठते है।
- **बाउंड्रीवॉल व गेट** : 88% स्कूल सुरक्षित चारदीवारी में। मवेशी, सड़क दुर्घटना और असामाजिक तत्वों से सुरक्षा मिली।

सुंदरीकरण बाल पेंटिंग

100% स्कूलों की बाहरी–भीतरी दीवारें चमकीली। बाला यानी 'Building as Learning Aid' के तहत दीवारों पर हिंदी–अंग्रेजी वर्णमाला, गिनती, पहाड़ा, नक्शा, विज्ञान चित्र बने हैं। बच्चा खेल–खेल में दीवार से सीखता है।

डिजिटल और तकनीकी सुविधाएं–गांव में 'स्मार्ट स्कूल'

स्मार्ट क्लासरूम योजना

- 15,000 लक्षित स्कूलों में से 12,850 में 55 इंच स्मार्ट LED टीवी, एंड्रॉयड बॉक्स, वायरलेस माइक–सेट इंस्टॉल। DIKSHA, शिक्षिक पोर्टल, ई–लॉट्स के 5000 वीडियो उपलब्ध।
- **उपयोग** : 83% स्कूलों में सप्ताह में 3 दिन स्मार्ट क्लास चल रही है। कक्षा 2 का बच्चा एनीमेशन से 'ए फॉर एप्पल' देखता है। 'पठन गति' बच्चों में पठन गति में विकास हुआ है साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ है।

शिक्षक टैबलेट एवं प्रेरणा पोर्टल

- **वितरण** : 2.8 लाख शिक्षकों को टैबलेट। 96.2% प्रधानाध्यापक और 90.1% सहायक शिक्षक के पास टैबलेट।
- **सुविधा** : छात्र उपस्थिति, MDM, निपुण असेसमेंट, DBT सत्यापन, अवकाश आवेदन–सब रियल टाइम

में।'कागजी रजिस्टर' का बोझ 80% कम। शिक्षक का समय 'पढ़ाने' में बढ़ा।

ICT लैब कक्षा 6–8

12,000 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 10–10 कंप्यूटर की लैब। 69% में प्रशिक्षित कंप्यूटर अनुदेशक। बेसिक कोडिंग, पेंट, MS Word सिखाया जा रहा। गांव का बच्चा अब 'माउस' से नहीं डरता वह तकनीकी कौशल और दक्षता सीख रहा। इस हेतु शिक्षकों को भी ट्रेनिंग प्रदान की गई है।

छात्र–केंद्रित प्रत्यक्ष लाभ की सुविधाएं

- ❖ DBT 1200 रुपये : यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता–मोजा, स्कूल बैग
- ❖ व्यवस्था : PFMS से सीधे अभिभावक के आधार लिंक खाते में 1200 रुपये प्रति छात्र।
- ❖ कवरेज 2025–26 : 1.87 करोड़ बच्चे। 15 मई तक 93.9% खातों में पैसा ट्रांसफर। साइज गड़बड़, गुणवत्ता खराब जैसी समस्याओं व शिक्षकों के एक्स्ट्रा कार्य से भी छूट मिली है।
- ❖ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, बैग, संदर्शिका शिक्षक डायरी

शिक्षकों की शैक्षिक दक्षता को लगातार बढ़ा रहा।

असेसमेंट : प्रेरणा पोर्टल पर दैनिक साप्ताहिक व कार्यपुस्तिका के माध्यम से। 'प्रेरणा लक्ष्य' हर कक्षा की दीवार पर।

'प्रेरणा तालिका' शिक्षक संदर्शिका और 'ध्यानाकर्षण मॉड्यूल'

हर बच्चे का नाम तालिका पर। लाल–पीले–हरे रंग से स्तर अंकित जो अभिभावक मीटिंग में दिखाया जाता है। 'ध्यानाकर्षण' मॉड्यूल से कमजोर बच्चे पर 1 घंटा अतिरिक्त कार्य किया जाता है। लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए अलग से कार्य पुस्तिकाओं द्वारा शिक्षकों द्वारा कार्य किया जा रहा है। ट्रेंड शिक्षकों द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है।

- **समयरेखा** : 12.5 करोड़ किताबें 12 अप्रैल तक 98.3% स्कूलों में। 'अभ्यास' कार्यपुस्तिका, बाल पत्रिका, लाइब्रेरी बुक। अब कार्यदिवस बर्बाद हुए बिना 'सत्र शुरू, किताब शुरू'।
- **गुणवत्ता** : कागज 70 GSM, रंगीन छपाई, वजन हल्का।
- **मध्यान्ह भोजन योजना** : पोषण का अधिकार 1.9 करोड़ बच्चे, 1.13 लाख स्कूल, 4.2 लाख रसोइया।
- **मेन्यू 2025–26** : दाल–चावल–सब्जी–रोटी तहरी मीनू के अनुसार। दूध, मौसमी फल। स्कूलों में पूर्ण पालन।

जियो–टैग फोटो अपलोड व जिला टास्क फोर्स द्वारा औचक निरीक्षण गुणवत्तापरक शिक्षा की सुविधाएं

निपुण भारत मिशन : FLN किट और असेसमेंट कक्षा 1–2 के 100% स्कूलों में 'जादुई पिटारा'– 20 तरह के TLM। बिग बुक, फ्लैश कार्ड, गणित किट, कहानी चार्ट, पोसमबी।

प्रशिक्षण : 2.4 लाख शिक्षकों ने NISHTHA 4.0 के 50 घंटे पूरे किए। अन्य प्रशिक्षण जो AI, ICT लैब और

नवीन और समावेशी सुविधाएं 2025–26,10 बैग–लेस डे

77.6% स्कूलों ने कैलेंडर लागू किया। बच्चा कुम्हार, बढ़ई, बैंक, थाना, डाकघर, मेंथा प्लांट, कृषि विज्ञान केंद्र जाता है। 'किताबी ज्ञान', 'जीवन का ज्ञान'। छम्च 2020 का एक्सपीरिएंशियल लर्निंग अब जमीन पर।

स्किल एजुकेशन कक्षा 6–8

15,000 स्कूल 'स्किल हब'। IT, इलेक्ट्रिक, हेल्थकेयर, रिटेल, एग्रीकल्चर, ब्यूटी–वेलनेस ट्रेड। 7.1 लाख बच्चे इनरोल्ड। 6 माह का सर्टिफिकेट। 71% बच्चों ने कहा– "पहली बार लगा स्कूल में करके सीख रहे हैं।"

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

जन्म से स्नातक तक 6 किश्तों में 15,000 रुपये। 2025–26 में 15.2 लाख नई लाभार्थी। 2019 से कुल 89

लाख बालिकाएं। कक्षा 9 में बालिका नामांकन 2019 के 74% से बढ़कर 83.4%।

APAAR ID: वन नेशन वन स्टूडेंट।

1.71 करोड़ यानी 90% बच्चों की डिजिटल अकादमिक ID बन गई। UDISE+ से लिंक। छात्रवृत्ति, ट्रांसफर, ड्रॉपआउट ट्रैकिंग आसान। 2030 तक 'क्रेडिट बेस्ड' पढ़ाई की नींव।

दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं

1,240 ब्लॉक संसाधन केंद्र। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ब्रेल किट, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड। 1.8 लाख CWSN बच्चे नामांकित। 4,200 स्पेशल एजुकेटर विशेष पुस्तकों एवं वर्कबुक से होम–बेस्ड एजुकेशन भी दे रहे।

शिक्षक कल्याण सुविधाएं

- अंतर्जनपदीय स्थानांतरण : 2024–25 में 68,000 शिक्षकों को गृह जनपद।
- कैशलेस चिकित्सा : 5 लाख तक मुफ्त इलाज।
- मिशन प्रेरणा ई–संबल : टैबलेट, डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन ट्रेनिंग।

बजटीय प्रावधान और मॉनिटरिंग सुविधा

बजट 2025–26: कुल 89,340 करोड़, राज्य बजट का 13.2%। वेतन 62,400 करोड़, MDM 4,200 करोड़, DBT 2,244 करोड़, समग्र शिक्षा 8,100 करोड़।

मॉनिटरिंग सुविधा : प्रेरणा ऐप, MDM IVRS, DBT डैशबोर्ड, शारदा पोर्टल, CM हेल्पलाइन 1076। DM, CDO, BSA के डैशबोर्ड पर रोज का डाटा भी उपलब्ध हो रहे हैं।

इस सुविधा से सशक्तीकरण की यात्रा में 2025–26 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग 'पहुंच' के मोर्चे पर 90% सफल है। शौचालय, बिजली, किताब, पैसा, टैबलेट–समय पर पहुंच रहा है। 'बिल्डिंग' 19 पैरामीटर से संतृप्त हो रही, विद्यालय सुविधा सम्पन्न बन गए हैं। सुविधा तभी सार्थक है जब अंतिम बच्चे तक 'सीखना' पहुंचे। 2025–26 का डाटा बताता है कि रास्ता और सुविधा मिल रही है। अब रफ्तार और बढ़ानी है। अब वह दिन दूर नहीं, जब हर बच्चा फर्राटेदार पढ़ेगा, AI व कोडिंग का ज्ञान होगा और टैबलेट पर सवाल पूछेगा, उस दिन 'बेसिक शिक्षा' में 'विकास की बुनियाद' कहलाएगी। ♦

मो. : 8737879848

(लेखिका शिक्षाविद् हैं)

अत्याधुनिक होते यूपी के शहर

—विमल पाठक

कभी पश्चिमी देशों में उपलब्ध आधुनिक एवं अद्यतन सुविधाओं को देखकर यह कल्पना की जाती थी कि क्या कभी ऐसी ही व्यवस्था हमारे देश–प्रदेश में होगी? लेकिन जनभावनाओं की इसी आकांक्षाओं को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में स्मार्ट सिटी मिशन की अवधारणा को धरातल पर उतारा। इस निर्णय के पीछे उनका उद्देश्य था कि भारत के भी नगर ऐसे बनें, जो पश्चिम देशों को देखकर अपनी कल्पनाओं में संजो रखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए देश के सबसे बड़े सूबे उप्र में राज्य की योगी सरकार ने 58 जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए कमर कस ली है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के विस्तार और संतुलित शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में "नवयुग पालिका योजना" को मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना के तहत 58 जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहली बार नगर निगमों से बाहर के नगरीय निकायों, विशेषकर जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को प्राथमिकता देते हुए विकास की नई रूपरेखा तैयार की है। योजना के अंतर्गत 55 नगर पालिका परिषदों, 3 नगर पंचायतों तथा गौतमबुद्धनगर की दादरी नगर पालिका परिषद को शामिल किया गया है।

योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 583.20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी, इस तरह 5 वर्षों (2025–26 से 2029–30) में कुल 2916 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। नवयुग पालिका योजना के माध्यम से स्मार्ट सिटी की

तर्ज पर डिजिटल गवर्नेन्स, ई–सेवाओं और तकनीकी समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नागरिक सेवाएं अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य नगरीय निकायों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना तथा नागरिकों के जीवन स्तर (ईज ऑफ लिविंग) में सुधार लाना है। इसके तहत सड़कों, जल निकासी, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं का व्यापक विकास किया जाएगा।

जिला मुख्यालयों को विकसित करने से विभिन्न मंडलों के बीच विकास असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी। इससे नगर निगमों से बाहर के क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित होगा। परियोजनाओं के चयन के लिए जनपद स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जबकि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण के बाद सक्षम स्तर से अनुमोदन दिया जाएगा। इसके बाद ही विकास कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार बड़े नगर निगमों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब जिला मुख्यालय स्तर के नगर पालिका क्षेत्रों को भी विकसित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास असमानता भी कम होगी और नागरिकों के जीवन स्तर (ईज आफ लिविंग) में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। इसके तहत सड़कों, जल निकासी, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं का व्यापक विकास किया जाएगा। जिला मुख्यालयों को विकसित करने से विभिन्न मंडलों के बीच विकास असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी। इससे नगर निगमों से बाहर के क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित होगा।

"नवयुग पालिका योजना" इसी सोच का परिणाम है। इसके अंतर्गत उत्सव भवन, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी केंद्र, पार्कों का विकास तथा विद्युत व्यवस्था के आधुनिकीकरण जैसे कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निकायों को उनकी जनसंख्या के आधार पर दो श्रेणियों (डेढ़ लाख से अधिक और डेढ़ लाख से कम आबादी) में विभाजित किया गया है, ताकि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा सके। ◆

मो. : 9984905555

(लेखक पत्रकार हैं)

किसानोन्मुख योगी सरकार

–अर्चना शुक्ला

यह सच है कि कृषि प्रधान देश में यदि किसान सुखी नहीं होगा तो जनता कभी न कभी उसके कोप से सदैव ग्रसित रहेगी। जाहिर है कि यह एक सार्वभौमिक सत्य जिससे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भलीभांति भिज्ञ हैं। तभी तो अभी हाल में हुए अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन, जिसे प्राकृतिक आपदा की संज्ञा दी जा सकती है, से अन्नदाता किसानों को हुई क्षति के लिए मुख्यमंत्री योगी स्वयं आगे आये और बाकायदा अपने अधीनस्थों एवं संबंधित अधिकारियों को सिर्फ निर्देश ही नहीं दिया बल्कि यह सुनिश्चित किया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को यथोचित एवं तत्समय सहायता उपलब्ध करायी जाये।

सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। सीएम योगी ने इस आपदा को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की। जिसमें उन्होंने कहा कि इस विपरीत परिस्थिति में अन्नदाता का चिंतित होना स्वाभाविक है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि बेमौसम बारिश और ओले गिरने से प्रभावित हुए हर किसान एवं बटाईदार के नुकसान का सटीक, निष्पक्ष एवं समयबद्ध आकलन कर तत्काल क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिला स्तर पर राजस्व, कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए जल्द सर्वेक्षण करके रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, ताकि राहत वितरण यानी मुआवजे में किसी प्रकार का विलंब न हो। सीएम योगी ने बीमा कंपनियों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर फसल बीमा दावों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी खुद किसानों से संपर्क कर उन्हें बीमा योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि हर जिले को राज्य आपदा राहत कोष से पर्याप्त धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान तेज

हवा के साथ आग लगने की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए निर्देश दिए कि जनहानि एवं पशुहानि की स्थिति में 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। संवेदनशीलता का उदाहरण यही है कि उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी और इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने किसी भी आपदा में जनहानि पर 24 घंटे के अंदर 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, पशु हानि की तत्काल भरपाई और आंधी, अग्निकांड या आपदा से प्रभावितों को तत्काल आवास उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए।

हालांकि यह भी एक अकाट्य सत्य है कि वर्षों बाद उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में एक ऐसी सरकार आयी जिसने सिर्फ बयानबाजी या फिर भाषणबाजी नहीं की बल्कि कृषि, उद्यान, गन्ना, चीनी और सिंचाई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। सरकार ने पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब अगेती किस्म 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म 390 रुपए प्रति क्विंटल है।

उल्लेखनीय है कि 2017 से अब तक गन्ना मूल्य में कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और गन्ना किसानों को 2.90 रुपए लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त 261.91 करोड़ रुपये की लागत से मोरना (मुजफ्फरनगर) की गंगा सहकारी चीनी मिल का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जा रहा है। उधर, किसानों को बीज की उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन देखने की सुविधा दी गई है। गौरतलब है कि यूपी देश के कुल 55 फीसदी गन्ने का उत्पादन कर रहा है, और एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग दो लाख करोड़ लीटर के करीब पहुंच गया है। इसके

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मत है कि पहले किसान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कारीगर और उद्यमी भी था। आक्रांताओं ने भारत की खेती के साथ–साथ उद्यमिता पर भी हमला किया, जिससे उत्पादक किसान कर्जदार बन गया और उद्यमी कारीगर भी कर्ज के बोझ तले दब गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक साजिश के तहत गांवों की आत्मनिर्भर इकाई को भंग किया गया। लेकिन राज्य सरकार ने कृषि और खेती को एजेंडा बनाया। पहले उत्तर प्रदेश में 10–10 वर्ष तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था, लेकिन आज प्रदेश देश का 55 प्रतिशत गन्ना उत्पादन करता है और एथनॉल उत्पादन में भी नंबर–1 है। 122 चीनी मिलों में से 107 मिलें अब 6–7 दिनों में भुगतान कर रही हैं। नई मिलें लगाने के लिए आने वाले निवेशकों को फिलहाल रोका जा रहा है, ताकि व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

अलावा सूबे में गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। इसके अतिरिक्त सरकार ने प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए वित्तीय सहायता और राहत प्रदान करने की तत्काल व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मत है कि पहले किसान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कारीगर और उद्यमी भी था। आक्रांताओं ने भारत की खेती के साथ–साथ उद्यमिता पर भी हमला किया, जिससे उत्पादक किसान कर्जदार बन गया और उद्यमी कारीगर भी कर्ज के बोझ तले दब गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक साजिश के तहत गांवों की आत्मनिर्भर इकाई को भंग किया गया। लेकिन राज्य सरकार ने कृषि और खेती को एजेंडा बनाया। पहले उत्तर प्रदेश में 10–10 वर्ष तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था, लेकिन आज प्रदेश देश का 55 प्रतिशत गन्ना उत्पादन करता है और एथनॉल उत्पादन में भी नंबर–1 है। 122 चीनी मिलों में से 107 मिलें अब 6–7 दिनों में भुगतान कर रही हैं। नई मिलें लगाने के लिए आने वाले निवेशकों को फिलहाल रोका जा रहा है, ताकि व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

यह सर्वविदित है कि 2014 से पहले देश में किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। पहले किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं था, उनका शोषण होता था और वे सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाते थे। बिचौलियों के हावी होने से किसानों को मजबूरन आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ता था। आज सरकार किसानों को उनकी लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम दे रही है। सिंचाई के लिए फ्री बिजली और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए उप्र के बिजली विभाग को हर वर्ष तीन हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वहीं, किसानों को सोलर पैनल से जोड़ने का प्रयास

जारी है। सरयू नहर परियोजना के तहत 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की गई है। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग दी जा रही है। हर गाय के भरण–पोषण के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि उत्पादन के साथ पोषण बढ़ाना चुनौती है। कम लागत में उत्पादन बढ़ाने, कृषि को टेक्नोलॉजी और डेटा से जोड़ने पर चर्चा जरूरी है. ड्रोन से छिड़काव, सैटेलाइट से भूमि और मौसम की निगरानी, एआई और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बीज विकसित करने की जरूरत है। मंडी शुल्क खत्म कर दिया गया है। अब 'लैब टू लैंड' नहीं, बल्कि 'लैब इन लैंड' की अवधारणा अपनानी होगी, यानी खेत ही प्रयोगशाला बने। प्राकृतिक खेती को एक मात्र विकल्प मानते हुए उनका मत है कि कुछ लोगों की नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण प्रकृति भी प्रभावित होती है। बकौल सीएम प्रदेश में वर्तमान में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। यदि केवीके सक्रिय रहेंगे तो सभी को लाभ मिलेगा। किसान खुशहाल होगा तो देश और समाज भी खुशहाल होगा। ◆

मो. : 8299336045

(लेखिका पत्रकार हैं)

योगी सरकार की योजना से बदली तकदीर

—पायल लक्ष्मी सोनी

कहते हैं कि जब व्यवस्था सही दिशा में काम करे, नीतियां जमीन पर उतरें और युवाओं के भीतर कुछ कर गुजरने की आग हो, तब साधारण घरों से असाधारण कहानियां जन्म लेती हैं। उत्तर प्रदेश की धरती इन दिनों ऐसी ही अनेक प्रेरक कहानियों की साक्षी बन रही है, जहां युवा अब केवल नौकरी की तलाश में शहरों की धूल नहीं छान रहे, बल्कि अपने गांव, अपने जिले और अपनी मिट्टी में अवसर खोज रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाई जा रही आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की योजनाओं ने हजारों युवाओं को नया आत्मविश्वास दिया है। इन्हीं सफल कहानियों में एक नाम है—लखीमपुर खीरी के ग्राम पहाड़ापुर निवासी अनिकेत वर्मा का।

अनिकेत वर्मा की कहानी केवल एक व्यक्ति की आर्थिक उन्नति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रमाण है जिसमें युवा हाथ फैलाने के बजाय हाथ देने वाला बनना चाहता है। यह कहानी बताती है कि यदि सही समय पर मार्गदर्शन, पूंजी और विश्वास मिल जाए, तो गांव का युवक भी उद्योगपति बन सकता है।

लखीमपुर खीरी का पहाड़ापुर गांव भी उन हजारों भारतीय गांवों जैसा ही है, जहां सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन साधन सीमित। ऐसे वातावरण में पले—बढ़े अनिकेत ने भी जीवन में आगे बढ़ने के अनेक सपने देखे। आम युवाओं की तरह उन्होंने भी नौकरी को सुरक्षित भविष्य माना। लेकिन समय के साथ उन्हें यह समझ आया कि नौकरी में सीमित आय है, सीमित अवसर हैं और सीमित स्वतंत्रता है। मन में कहीं न कहीं यह इच्छा थी कि कुछ अपना किया जाए, ऐसा कार्य हो जिसमें सम्मान भी हो और दूसरों को भी अवसर मिले।

यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उनके जीवन में आशा की किरण बनकर आई। यह योजना केवल ऋण योजना नहीं, बल्कि उन युवाओं के लिए अवसर का द्वार है जो काम करना चाहते हैं लेकिन पूंजी के अभाव में रुक जाते हैं। अनिकेत वर्मा ने इस योजना के बारे में जानकारी ली, प्रक्रिया समझी और आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

दिसंबर 2025 में जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से उन्हें 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। यह वह मोड़ था जहां सपना कल्पना से निकलकर वास्तविकता की जमीन पर उतर आया। कई लोग अवसर मिलने पर भी डर जाते हैं, लेकिन अनिकेत ने जोखिम उठाया। उन्होंने इस धनराशि को खर्च नहीं किया, बल्कि

निवेश में बदला। यही सोच सफल लोगों को अलग बनाती है।

अनिकेत ने छोटे स्तर पर चल रहे अपने कार्य को व्यवस्थित उद्योग का रूप देने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी यूनिट में 6 ऑटोमेटिक मशीनें स्थापित कीं। गांव के वातावरण में मशीनों की आवाज केवल उत्पादन की ध्वनि नहीं थी, वह आत्मनिर्भर भारत की घोषणा थी। जहां कभी रोजगार के लिए लोग बाहर जाते थे, वहीं अब रोजगार गांव में पैदा हो रहा था।

उन्होंने वाशिंग पाउडर निर्माण का कार्य शुरू किया। यह ऐसा उत्पाद है जिसकी बाजार में निरंतर मांग रहती है। घरेलू उपयोग की वस्तु होने के कारण इसकी खपत स्थायी रहती है। अनिकेत ने बाजार की जरूरतों को समझा और उत्पादन को उसी अनुसार ढाला। उनका उत्पाद आधा किलो, 1 किलो और 3 किलो की पैकिंग में तैयार होने लगा, ताकि हर वर्ग और हर ग्राहक तक पहुंच बनाई जा सके।

किसी भी उद्योग की सफलता केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि गुणवत्ता, पैकेजिंग, आपूर्ति और भरोसे पर भी टिकी होती है। अनिकेत ने इन सभी पक्षों पर ध्यान दिया। वे कानपुर से कच्चा माल मंगवाते हैं, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। धीरे–धीरे उनका वाशिंग पाउडर स्थानीय बाजार में अपनी पहचान बनाने लगा। ग्राहक जब एक बार संतुष्ट हुआ, तो उसने दोबारा वही उत्पाद मांगा। यही किसी भी ब्रांड की पहली जीत होती है।

आज अनिकेत वर्मा केवल स्वयं कमाने वाले युवक नहीं हैं। उन्होंने 7 लोगों को रोजगार भी दिया है। गांव के सात परिवारों में आज नियमित आय पहुंच रही है। किसी एक व्यक्ति की सफलता जब कई घरों की रसोई जलाने लगे, तभी वह वास्तविक सफलता कहलाती है।

उनकी यूनिट में काम करने वाले लोग केवल मजदूर

नहीं, बल्कि परिवर्तन के सहभागी हैं। गांव के युवाओं को अब यह दिखाई देने लगा है कि मेहनत और सही योजना के साथ गांव में भी सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है। शहर जाना ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है।

व्यवसाय में लागत, परिवहन, मजदूरी, पैकेजिंग और अन्य खर्चों के बाद अनिकेत वर्मा की शुद्ध मासिक आमदनी 50 से 60 हजार रुपये है। यह आय केवल संख्या नहीं है, यह उस युवक की जीत है जिसने सीमित सोच को तोड़ा। नौकरी छोड़कर मालिक बनने का साहस किया और अब स्थिर आय के साथ सामाजिक पहचान भी अर्जित की।

आज गांव में लोग उन्हें अलग नजर से देखते हैं। युवा उनसे सलाह लेते हैं। बुजुर्ग उनकी प्रशंसा करते हैं। परिवार को उन पर गर्व है। यह सम्मान धन से बड़ा होता है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य भी यही है कि प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में नए उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र आधारित व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण रियायती ब्याज दरों पर दिया जाता है, जो बाजार दरों से कम है। इस धनराशि का उपयोग प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय, कार्यशील पूंजी और अन्य संबंधित खर्चों में किया जा सकता है।

सरकार की योजनाएं तभी सफल मानी जाती हैं जब वे कागज से निकलकर समाज की धड़कनों तक पहुंचें। अनिकेत वर्मा जैसी कहानियां बताती हैं कि योजनाएं यदि ईमानदारी से लागू हों तो उनका असर गहरा होता है।

आज देश में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी नहीं, बल्कि दिशा की कमी है। बहुत से युवा प्रतिभाशाली हैं, पर उन्हें पता नहीं कि शुरुआत कहां से करें। अनिकेत की यात्रा बताती है कि शुरुआत जानकारी से होती है, फिर निर्णय से और अंततः परिश्रम से।

यदि लखीमपुर खीरी के एक गांव का युवक उद्योग खड़ा कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी युवा कर सकता है। आवश्यकता है कि योजनाओं की जानकारी ली जाए, जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र से संपर्क किया जाए, व्यवसाय का चयन सोच–समझकर किया जाए और मेहनत से पीछे न हटें।

अनिकेत वर्मा की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है–जहां गांवों में मशीनें चल रही हैं, युवाओं के सपने आकार ले रहे हैं और आत्मनिर्भरता नारा नहीं,बल्कि वास्तविकता बन रही है।

जब इतिहास लिखा जाएगा, तब यह भी दर्ज होगा कि एक समय ऐसा आया था जब उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी की कतार से निकलकर उद्योग की कतार में खड़ा हो गया था। अनिकेत वर्मा उसी परिवर्तन के जीवंत प्रतीक हैं। ◆

मो. : 9140385403

(लेखिका साहित्यकार एवं पत्रकार हैं)

उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्रांति की नई उड़ान

–देवराज सिंह

उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन देखा है, वह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। साल 2022 के बाद से पर्यटन ढांचे में व्यापक सुधार, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और ऐतिहासिक–धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास ने यूपी को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूत बनाया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में "आस्था और अर्थव्यवस्था" का संतुलित मॉडल अब जमीनी हकीकत बन चुका है, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है।

पर्यटन नीति–2022 से बदली तस्वीर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू पर्यटन नीति–2022 ने राज्य में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा दी है। इस नीति के तहत होटल, होमस्टे, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर और ईको–टूरिज्म समेत 22 क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया। बेहतर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस–वे नेटवर्क और मजबूत कानून–व्यवस्था ने पर्यटकों का भरोसा बढ़ाया है। यही वजह है कि यूपी अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है।

पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि

पिछले वर्षों के आंकड़े इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। 2017 में जहां लगभग 23.75 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए थे, वहीं 2024 तक यह संख्या बढ़कर 64.91 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2025 में महाकुंभ के आयोजन ने इस रिकॉर्ड को और ऊंचाई दी, जहां कुल पर्यटकों की संख्या 156 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। वर्तमान में देश के कुल घरेलू पर्यटन में यूपी की हिस्सेदारी लगभग 21.9 प्रतिशत हो चुकी है, जो इसे भारत का नंबर–1 पर्यटन राज्य बनाती है।

धार्मिक स्थलों का भव्य विकास

धार्मिक स्थलों के विकास में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहर की पहचान बदल दी है। यहां पर्यटकों

की संख्या 2017 के 2.84 लाख से बढ़कर 2024 में 16 करोड़ से अधिक हो गई।

इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और प्रयागराज में संगम क्षेत्र का विकास श्रद्धालुओं के अनुभव को नया आयाम दे रहा है। मथुरा–वृंदावन क्षेत्र में भी ब्रज सर्किट के तहत व्यापक सुधार हुए हैं।

सर्किट आधारित पर्यटन और विरासत संरक्षण

राज्य में रामायण, कृष्ण, बौद्ध, जैन और सूफी जैसे 12 से अधिक पर्यटन सर्किट विकसित किए गए हैं। इन सर्किटों के माध्यम से धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ा गया है, जिससे पर्यटकों को एक समग्र अनुभव मिलता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू पर्यटन नीति–2022 ने राज्य में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा दी है। इस नीति के तहत होटल, होमस्टे, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर और ईको–टूरिज्म समेत 22 क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया। बेहतर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस–वे नेटवर्क और मजबूत कानून–व्यवस्था ने पर्यटकों का भरोसा बढ़ाया है। यही वजह है कि यूपी अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है।

सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, मेरठ में 1857 संग्रहालय और गोरखपुर में शहीद स्मारक जैसी परियोजनाएं विकसित की गई हैं।

निवेश और रोजगार के नए अवसर

पर्यटन नीति–2022 के तहत अब तक 36,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित हुआ है। इससे 1,600 से ज्यादा पर्यटन इकाइयां स्थापित हुई हैं और करीब 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। खास बात यह है कि इनमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

इको–टूरिज्म और ग्रामीण विकास

पर्यटन को शहरों से बाहर ले जाने

के लिए यूपी इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। दुधवा नेशनल पार्क, कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नाइट स्टे, सफारी और नेचर ट्रेल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। 49 इको–टूरिज्म परियोजनाओं और 200 से अधिक गांवों को ग्रामीण पर्यटन से जोड़ा गया है।

फेस्टिवल इकॉनमी का प्रभाव

'टेंपल एंड फेस्टिवल इकॉनमी' मॉडल ने यूपी को नई पहचान दी है। दीपोत्सव, देव दीपावली और ब्रज की होली जैसे आयोजन अब वैश्विक आकर्षण बन चुके हैं। ये आयोजन न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं, बल्कि होटल, परिवहन और व्यापार को भी मजबूती देते हैं। साल 2022 के बाद उत्तर प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में जो परिवर्तन देखा है, वह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास के संगम ने यूपी को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में हाल के वर्षों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और प्रयागराज में कुंभ व महाकुंभ जैसे आयोजनों ने तीर्थ पर्यटन को अभूतपूर्व गति दी है। इन परियोजनाओं के कारण देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। योगी सरकार का यह विकास मॉडल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। वर्ष 2017 से 2025 के बीच प्रदेश के 197 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया, जिससे पर्यटन आधारित व्यापार और रोजगार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

प्रदेश में त्योहारों और उत्सवों को भी भव्य स्वरूप दिया गया है। अयोध्या का दीपोत्सव, वाराणसी की देव दीपावली और मथुरा–बरसाना की होली अब वैश्विक आकर्षण बन चुके हैं। विशेष रूप से महाकुंभ–2025 में आए 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके अलावा ललितपुर का लखरी मेला, बुलंदशहर का कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान, मेरठ का नौचंदी मेला और आगरा का बटेश्वर पशु मेला जैसे क्षेत्रीय आयोजन भी अब बड़े स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। इन आयोजनों से होटल, परिवहन, खुदरा व्यापार और सेवा क्षेत्र को सीधा लाभ मिल रहा है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पर्यटन विस्तार उत्तर प्रदेश को वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। ◆

मो. : 945000913

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

यूपी के सपनों का गंगा एक्सप्रेस वे

—सियाराम पांडेय 'शांत'

जर्जर और बदहाल सड़कें कभी उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थीं। दूसरे राज्यों के लोग मजाकिया अंदाज में कहा करते थे कि जहां से सड़कों में गड्ढे मिलने लगें और वाहन हिचकोलें खाने लगें तो समझ लें कि उत्तर प्रदेश आ गया है लेकिन वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद यह अवधारणा बदली है। सड़कें किसी भी राज्य की प्रगति का आईना होती हैं, इस विचारधारा पर काम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन से काम करना शुरू कर दिया था। आज हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव और नगर संपर्क मार्ग से जुड़ गए हैं। विगत नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ एक्सप्रेस वे हब के रूप में उभरा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण से उत्तर प्रदेश के विकास को चार चांद लगे हैं। राज्य के औद्योगिक व अवस्थापना विकास की गति दोगुनी हुई है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के कुल एक्सप्रेस वे में से सर्वाधिक 60 प्रतिशत एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। गंगा एक्सप्रेस–वे के शुरू होने से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन न केवल बेहद आसान हो गया है बल्कि जैन सर्किट, महाभारत सर्किट और 'कल्कि धाम' संभल के अतिरिक्त मार्ग के आसपास के इको–टूरिज्म स्थलों को भी नई ऊर्जा मिल रही है। अगर यह कहें कि गंगा एक्सप्रेस–वे केवल सड़क नहीं, राज्य के सपने की मूर्त अभिव्यक्ति है तो कदाचित गलत नहीं होगा। गंगा एक्सप्रेस वे से मेरठ और प्रयागराज की दूरी 10–12 घंटे से घटकर महज 5 घंटे रह गई है। गंगा एक्सप्रेस वे की आपातकालीन एयरस्ट्रिप भारतीय वायु सेना के लिए भी मददगार साबित

हो सकती है। आपात स्थिति में वायुसेना के लडाकू विमान यहां आसानी से उतर सकते हैं और यहां से उड़ान भर सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो गंगा एक्सप्रेस वे यातायात ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत अहम भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण का सपना देखा था, वह सपना न केवल सच हो गया बल्कि देश को मूर्त रूप में समर्पित भी हो गया। एक्सप्रेस वे की निर्माण यात्रा यह बताने और जताने के लिए काफी है कि इरादे अगर बुलंद हों और योजनाओं का क्रियान्वयन नेकनीयती व ईमानदारी से हो तो कुछ भी मुमकिन है।

माना तो यह भी जा रहा है कि कि गंगा एक्सप्रेस वे के शुभारंभ से उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी आएगी। राज्य के विकास की गति में इजाफा होगा। 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ही देख लिया था और 29 अप्रैल 2026 को यह न केवल पूर्ण हो गया अपितु देश को समर्पित भी हो गया। पीपीपी मॉडल, मल्टी–पैकेज निर्माण और आधुनिक तकनीक की मदद से बने इस एक्सप्रेस वे के मार्ग में भूमि अधिग्रहण, कोविड और तकनीकी चुनौतियां भी कम नहीं आईं लेकिन इन सबके बावजूद निर्माण एक बार शुरू हुआ तो थमा नहीं और आज उसकी सुखद परिणिति हम लोगों के समक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण कर दिया है। विकथ्य है कि 18 दिसंबर, 2021 को उन्होंने ही इसका शिलान्यास भी किया था।

गंगा एक्सप्रेस वे के लोकार्पण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास मॉडल की झलक भी देखी। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन तो किया ही, प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेस वे नेटवर्क, औद्योगिक संभावनाओं और सांस्कृतिक विरासत के संगम की विस्तृत जानकारी भी हासिल की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं प्रधानमंत्री को प्रदेश में तैयार हो रहे एक्सप्रेस वे नेटवर्क, उनकी रणनीतिक उपयोगिता और भविष्य की योजनाओं की विशद जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस व्यापक नेटवर्क को नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला करार दिया। यूपीडा की प्रदर्शनी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रही, अपितु इसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भी नजर आई। प्रयागराज महाकुंभ संगम, आर्ट गैलरी, प्रतापगढ़ का पक्षी अभ्यारण्य, महात्मा बुद्ध की ध्यानमग्न प्रतिमा और विभिन्न मंदिरों की आकर्षक झांकियों ने भी प्रधानमंत्री का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रदर्शनी से यह बात पूरी तरह ध्वनित हुई कि यूपी विकास की ओर तो तेज रफ्तार से बढ़ ही रहा है, परंपरा व संस्कृति को भी समान महत्व दे रहा है। प्रदर्शनी में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की पूरी प्रक्रिया, इसके मार्ग में आने वाले 12 जिलों और इससे मिलने वाली कनेक्टिविटी पर भी प्रकाश डाला गया। प्रदर्शनी में यह भी बताया गया कि यह एक्सप्रेस वे न केवल यात्रा को सरल और सुगम बनायेगा बल्कि लोगों के श्रम, समय और धन की भी बचत

करेगा। क्षेत्रीय संतुलित विकास का माध्यम भी बनेगा। यूपीडा की प्रदर्शनी में गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित किए जाने वाले औद्योगिक गलियारों (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) और लॉजिस्टिक्स हब की विस्तृत योजना भी प्रस्तुत की गई। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदर्शनी में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि गंगा एक्सप्रेस वे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिवर्तन का आधार बनने जा रहा है। औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय संतुलन के माध्यम से यह परियोजना प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी।

मेरठ से प्रयागराज तक फैला गंगा एक्सप्रेस वे केवल एक हाईवे नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का नया सुपर कॉरिडोर बनकर उभरा है। यह एक्सेस–कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हाई–स्पीड कनेक्टिविटी के साथ प्रदेश को एक्सप्रेस वे स्टेट के रूप में स्थापित कर रहा है। 120 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वाला यह प्रोजेक्ट यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाते हुए विकास की नई इबारत लिख रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे को आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। 6 लेन के इस एक्सप्रेस वे पर 14 दीर्घ सेतु, 165 लघु सेतु, 7 आरओबी, 32 फ्लाईओवर, 453 अंडरपास और 795 बॉक्स कल्वर्ट बनाए गए हैं। प्रमुख मार्गों से बेहतर संपर्क के लिए 21 स्थानों पर इंटरचेंज विकसित किए गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह निर्बाध रहेगा। इस परियोजना की एक विशेषता यह भी है कि इसे भविष्य की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। आने वाले वर्षों में ट्रैफिक लोड बढ़ने की स्थिति में इसे आसानी से 6 से 8 लेन में तब्दील किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने हरदोई के मल्लावां में 594 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के बाद अपने सम्बोधन में उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए जो बातें कहीं, वे काबिलेगौर हैं। उनके मुताबिक, पिछली सरकारों के कार्यकाल में हरदोई से भी किसी एक्सप्रेसवे के गुजरने की कल्पना नहीं की जा सकती थी लेकिन यह काम सिर्फ भाजपा की सरकार में ही संभव हुआ है। आज यूपी एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा लक्ष्य है लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी की क्षमता उत्तर प्रदेश के साथ है। इसका इस्तेमाल हम उत्तर प्रदेश को उत्पादन हब बनाने के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने पुरानी सियासत को भी बदला है और नई पहचान भी बनाई है।

प्रधानमंत्री की मानें तो उत्तर प्रदेश में निवेश आयेगा तो नए उद्योग और कारखाने लगेंगे और आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी विजन को केंद्र में रखकर बीते वर्षों में लगातार काम हुआ है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान पहले पलायन से होती थी, आज उसे इन्वेस्टर्स समिट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है।आज अगर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है तो उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास भारत की सामरिक ताकत भी बन रहा है। बड़ी–बड़ी डिफेंस कंपनियों के अपने कारखाने लगाने से छोटे–छोटे उपकरण बनाने वाले कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री के इस आश्वासन ने कि जल्द ही गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार भी किया जाएगा और उसका दायरा मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक कर दिया जाएगा। इसका और उपयोग हो सके, इसलिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा। जब उन्होंने यह कहा कि डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय पर उसका लोकार्पण भी होता है। रही बात यूपी के विकास की तो उसकी रफ्तार उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस से भी कहीं ज्यादा है तो लोग फूले नहीं समाए। बकौल प्रधानमंत्री आज यूपी में पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और 21 हवाई अड्डे हैं। एक्सप्रेसवे महज एक उच्च गति वाली सड़क नहीं है, बल्कि यह नई संभावनाओं, नए सपनों और नए अवसरों का गेटवे भी है। गंगा एक्सप्रेस से जुड़ने वाले उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और उनके आसपास के अन्य जनपदों के करोड़ों लोगों का जीवन भी इससे बदलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से किसान अपनी फसलों को और

उत्पादक अपने उत्पादों को अतिशीघ्र अपने पसंद के बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। इससे खेती के लिए जरूरी ढांचागत विकास संभावनाओं का विस्तार होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। नए उद्योग आने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण में किसानों के योगदान का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने तहे दिल से स्वीकार किया कि एक लाख से अधिक किसानों ने इस परियोजना के लिए जमीन मुहैया कराई, जिससे इसका समय पर निर्माण संभव हो सका। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी, 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे अन्नदाता किसानों की उन्नति, युवाओं के रोजगार, आस्था एवं संस्कृति के संरक्षण तथा उत्तर प्रदेश की समृद्धि का प्रमुख माध्यम बनेगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। बकौल मुख्यमंत्री, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स हब बनाए जा रहे हैं, जो आवागमन को तेज करने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। यह एक्सप्रेस वे न केवल परिवहन को सुगम बनाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। इस परियोजना के लिए राज्य के 12 जिलों की तकरीबन 18 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है, जबकि एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित करने के लिए लगभग 7 हजार एकड़ भूमि अलग से चिह्नित की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानें तो गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होगा। सड़क संपर्क, कृषि विपणन तथा क्षेत्रीय विकास को मजबूती प्रदान करेगा। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को गति देगा। वे यहीं रुकते। इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि दिल्ली–मेरठ के बीच देश की पहली रैपिड रेल के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री ने दूरियों को सीमित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। एक्सप्रेस वे, रैपिड रेल, इनलैंड वॉटरवेज, मेट्रो और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं राज्य की अपार संभावनाओं को निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।

उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे केवल दूरी और यात्रा की अवधि कम करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके साथ रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण कॉरिडोर जैसी बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं भी जुड़ी हैं, जिससे ये अन्नदाता किसानों की उन्नति, युवाओं के रोजगार, आस्था और संस्कृति के संरक्षण तथा प्रदेश की समग्र समृद्धि के सशक्त माध्यम बन रहे हैं। वैसे भी उत्तरप्रदेश जिस रफ्तार से विकास और विरासत के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह निकट भविष्य में उसे देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होगी। ◆

मो. : 7459998968

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

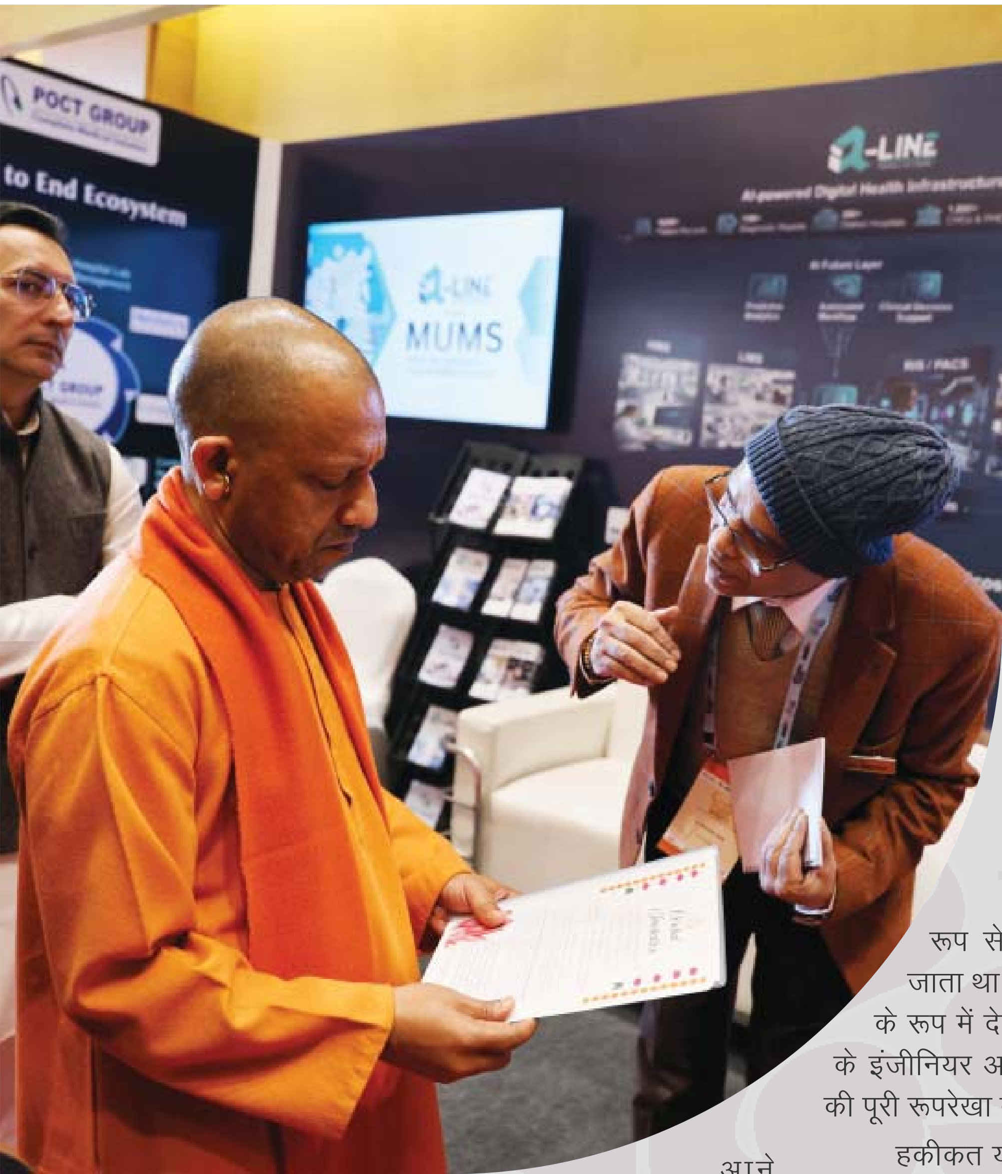

एआई सुपर पावर बनता उत्तर प्रदेश

—अजय श्रीवास्तव

आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के एआई (आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस) एक्सपर्ट की मांग दुनिया के विकसित देशों की प्राथमिकता बनने जा रही है। सबसे दिलचस्प यह है कि अपने देश के कई शहरों में ऐसे ग्लोबल प्लेटफार्म्स विकसित कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हमारे एक्सपर्ट दुनियाभर की लगभग प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि युद्ध के हालात और आर्थिक मंदी के बीच भारत जैसे शांतिप्रिय और हर दृष्टि से सुरक्षित देश में प्रोफेशनल्स कहीं ज्यादा क्षमता और सुकून से अपने कार्य को अंजाम दे सकेंगे।

दरअसल, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का सफर लेबर उपलब्ध कराने से शुरू होकर आज ग्लोबल लीडरशिप की दहलीज पर पहुंच चुका है। आज के हालात भले पहले जैसे न हों, लेकिन यह कहना गलत होगा कि मांग कम हुई है। बस, मांग का स्वरूप बदल गया है। पहले यूपी को मुख्य रूप से बैक–ऑफिस या सपोर्ट के लिए जाना जाता था। अब दुनिया अपने राज्य को इनोवेशन हब के रूप में देखती है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियर अब कोड लिख ही नहीं रहे, बल्कि प्रोडक्ट की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश अब एआई सुपरपावर बनकर निकट भविष्य में पूरे देश का 'ग्रोथ इंजन' बनने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में 'टेक्नोलॉजी' ही सबसे बड़ा स्तंभ है। इस स्तम्भ को हमारे एआई प्रोफेशनल्स चकाचौंध करेंगे।

सच पूछा जाए तो भविष्य में लखनऊ की पहचान नवाबों के शहर से ही नहीं, बल्कि भारत की पहली एआई सिटी से होने जा रही है। इस क्रम में नदवा रोड (अमौसी एयरपोर्ट के पास) पर लगभग 70–100 एकड़ में एआई सिटी विकसित की जा रही है। यहां दुनिया की बड़ी एआई कंपनियों के लिए डेटा सेंटर, रिसर्च लैब और इनोवेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य लखनऊ को दुनिया के टॉप 20 एआई हब में शामिल करना है।

वहीं, यूपी का नोएडा और ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर की राजधानी बनता जा रहा है। स्वाभाविक एआई को चलाने के लिए भारी मात्रा में 'डेटा' और 'कंप्यूटिंग पावर' की जरूरत

होती है। ग्रेटर नोएडा में 'योट्टा डी वन' जैसे हाइपर–स्केल डेटा सेंटर पहले ही चालू हो चुके हैं। यहां 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। इतना ही नहीं नोएडा क्षेत्र अब चिप व सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में भी आगे बढ़ रहा है, जो एआई हार्डवेयर के लिए बहुत जरूरी है।

वास्तव में उत्तर प्रदेश के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्कफोर्स है। इस नजर से देखें तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, ट्रिपल आईटी लखनऊ और मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों का फोकस अब विशेष रूप से एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज पर है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मिशन के लिए खासी व्यवस्था की है, ताकि यहां का युवा कोडिंग के साथ–साथ एआई एथिक्स और मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट बन सके।

देखा जाए तो केवल नोएडा ही नहीं, बल्कि अब वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में योगदान दे रहे हैं। कानपुर शहर ड्रोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी का केंद्र बन रहा है, जहां एआई का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। वाराणसी में एआई का उपयोग स्मार्ट सिटी और एग्रो–टेक (कृषि तकनीक) में किया जा रहा है।

पीछे मुड़कर देखें तो जेनरिक कोडिंग जैसे बेसिक जावा या सी प्लस–प्लस का दौर अब जा रहा है। आज अमरीका और यूरोप में उन इंजीनियर्स की भारी मांग है जो आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाऊड कम्प्यूटिंग यानी (एडब्ल्यूएस/अज्योर) और साइबर सिक्योरिटी में माहिर हैं। बस आवश्यकता है पुराने प्रोफेशनल्स खुद को अपडेट करते रहें, ऐसे में न केवल उनके लिए अवसर और खुलेंगे बल्कि नवीनतम स्किल्ड के साथ उनका सैलरी पैकेज और डिमांड दोनों रिकॉर्ड स्तर पर होगी।

खास पहलू यह है कि पहले भारतीय इंजीनियर्स को अमरीका जाना पड़ता था (एच–वनबी वीजा के जरिए)। वर्तमान स्थिति सुखद है। अब कंपनियाँ खुद भारत आ रही हैं। भारत में डेढ़ हजार से कहीं ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। ये विदेशी कंपनियों के ऐसे ऑफिस हैं जहाँ से पूरी दुनिया का कामकाज संभाला जाता है। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु में बैठकर वही काम कर रहा है और वही वैश्विक प्रभाव डाल रहा है, जो पहले सिलिकॉन वैली में रहकर संभव था।

जमीनी स्थिति समझी जाए तो एक समय था जब सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर का एकमात्र लक्ष्य अमरीका जाना होता था। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अब प्रतिभावान युवा भारत में ही रुककर अपनी कंपनियां (यूनिकॉर्न) बना रहा है। इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय टैलेंट को हायर करना और भी महंगा और प्रतिस्पर्धी हो गया है।

ताजा वैश्विक हालात में स्थिति थोड़ी जटिल भी हैं। पिछले एक–दो वर्षों में गूगल, मेटा, और अमेजन जैसी कंपनियों ने बड़े स्तर पर छंटनी की है। इसका असर भारतीय इंजीनियर्स पर भी पड़ा है। एक पुराना सूत्रवाक्य है आवश्यकता अविष्कार की जननी है, ऐसे में यह समझना ही होगा कि हम निरंतर अविष्कार कर रहें हैं, बस आवश्यकता है इसे अपनाने की और इसके लिए के लिए तेजी से कदम बढ़ाने की जरुरत है।

ताजा वैश्विक हालात में स्थिति थोड़ी जटिल भी हैं। पिछले एक–दो वर्षों में गूगल, मेटा, और अमेजन जैसी कंपनियों ने बड़े स्तर पर छंटनी की है। इसका असर भारतीय इंजीनियर्स पर भी पड़ा है। एक पुराना सूत्रवाक्य है आवश्यकता अविष्कार की जननी है, ऐसे में यह समझना ही होगा कि हम निरंतर अविष्कार कर रहे हैं, बस आवश्यकता है तो इसे अपनाने की और इसके लिए के लिए तेजी से कदम बढ़ाने की है।

मौजूदा स्थिति यह है कि संख्या से ज्यादा गुणवत्ता का महत्व बढ़ गया है। दुनिया को अब सिर्फ सॉफ्टवेयर लेबर नहीं चाहिए, बल्कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट चाहिए। ग्रोथ इंजन यूपी के साथ भारत आज भी दुनिया की सॉफ्टवेयर फैक्ट्री है और अब इस फैक्ट्री में स्मार्ट मशीनें और इनोवेटिव दिमाग तैयार हो रहे हैं। अगर एक भारतीय इंजीनियर के पास लेटेस्ट तकनीक का ज्ञान है, तो उसकी मांग आज भी अमरीका और दुनिया भर में उतनी ही मजबूत अर्थव्यवस्था है।

यूपी सरकार के नेतृत्वकर्ता और विभागीय अफसरों के प्रयासों से आने वाले समय में यूपी में एआई एक्सपर्ट्स की फौज होगी और विकसित देश भी इन एक्सपर्टस पर निर्भर होंगे। वर्तमान संकेत और आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में ग्लोबल एआई टैलेंट फैक्ट्री बनने की राह पर हैं। वर्तमान में यह केवल एक संभावना नहीं बल्कि वास्तविकता बनती दिख रही है। इसके पीछे तमाम ठोस कारण भी हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि हमारे पास युवाओं की जो संख्या है, वह किसी भी अन्य देश के पास नहीं है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी दुनिया में सबसे बड़ी अधिक एआई स्किल्ड युवा यहां तैयार हो रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार का इंडिया एआई मिशन जिसके लिए 10,000 करोड़ रु. से अधिक का बजट रखा गया है, स्कूल और कॉलेज स्तर से ही एआई शिक्षा को अनिवार्य बना रहा है। इससे अगले कुछ वर्षों में लाखों की संख्या में एआई–नेटिव प्रोफेशनल्स तैयार होंगे।

गहराई से समझें तो विकसित देशों की निर्भरता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि भारतीय इंजीनियर्स अब सिर्फ कोड नहीं लिख रहे। बल्कि उनमें जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता है। ओपन एआई की ताजा रिपोर्ट में है कि हम रिजनिंग टोकन्स यानि जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता के उपयोग में दुनिया के टॉप 5 देशों में है। यानी हमारे एक्सपर्ट्स अब एआई का उपयोग जटिल वैज्ञानिक और व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहे हैं।

कुल मिलाकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाला दशक हमारे एआई एक्सपर्ट्स का होगा। जैसे कभी हमने 'वाईटूके' संकट के समय दुनिया को बचाया था, वैसे ही भविष्य की एआई इकॉनमी के इंजन को चलाने वाले सबसे ज्यादा हाथ भारतीय होंगे जिसमें यूपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित देश अपनी तकनीकी रीढ़ के लिए यूपी पर बहुत हद तक निर्भर रहेंगे।

हकीकत यह है कि अगर भारत को दुनिया का 'एआई

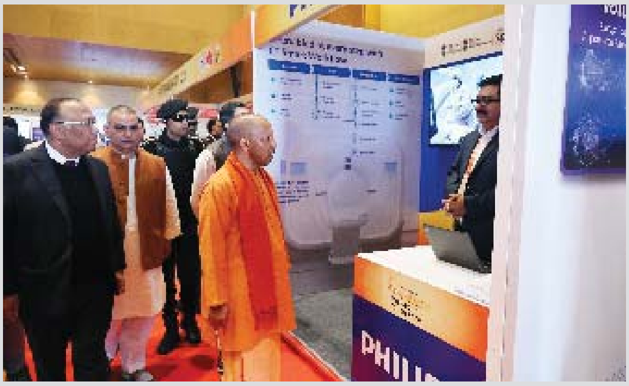

एक्सपर्ट' बनना है, तो बिना उत्तर प्रदेश के यह संभव नहीं है। यूपी न केवल 'एक्सपर्ट्स की फौज' देगा, बल्कि उन एक्सपट्र्स को काम करने के लिए विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर (एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स और डेटा सेंटर्स) भी उपलब्ध करा रहा है। अब वह समय दूर नहीं जब सिलिकॉन वैली की कंपनियाँ नोएडा और लखनऊ में अपने एआई ब्रेन सेट करेंगी।

सारी बातों का निचोड़ यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्णायक छलांग लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट 2026–27 के माध्यम से योगी सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आईटी सेक्टर को नई दिशा देने वाली कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है, जिनसे प्रदेश डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा।

उत्तर प्रदेश एआई मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो इंडिया एआई मिशन और इंडिया एआई डेटा लैब को आगे बढ़ाते हुए शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित करेगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर और डेटा सेंटर क्लस्टर को सुदृढ़ कर प्रदेश को सुरक्षित डेटा भंडारण और क्लाउड सेवाओं का बड़ा हब बनाने की योजना है।

उत्तर प्रदेश में नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों के उच्चीकरण से तकनीकी शिक्षा को मजबूती दी जाएगी। नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन के तहत रोबोटिक्स, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारा लक्ष्य सामान्य जनता के साथ–साथ राज्य सरकारों में एआई, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना है। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और संवेदनशील राज्य में स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान केवल समयबद्ध, प्रौद्योगिकी–चालित और उत्तरदायी मॉडल के माध्यम से ही संभव है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हम प्रारंभिक निदान, क्रिटिकल केयर और डेटा–आधारित निर्णय लेने को मजबूत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को एआई–नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीय मॉडल बनाना है। ◆

मो. : 7052084404
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हरित संकल्प

आज की सदी का सबसे बड़ा प्रश्न आर्थिक मंदी या कूटनीति नहीं, बल्कि हमारी धरती का निरंतर बढ़ता तापमान और असंतुलित होता पर्यावरण है। प्रकृति हमें बार–बार चेतावनी दे रही है–चाहे वह असमय आती बाढ़ हो, पिघलते हिमनद हों या बेतहाशा बढ़ती गर्मी। ऐसे निर्णायक समय में, जब वैश्विक मंचों पर केवल कागजी समझौते होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने 'सक्रिय संरक्षण' की नीति अपनाकर एक नई मिसाल पेश की है। उनका विजन स्पष्ट है–प्रगति वैसी ही हो जो प्रकृति का गला न घोंटे। मुख्यमंत्री ने अपने शासन के केंद्र में 'जलवायु न्याय' को रखा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, लेकिन पर्यावरण की बलि देकर नहीं।

–सौम्या मिश्रा

विजन : नीतिगत साहस और दूरगामी लक्ष्य

मुख्यमंत्री का मानना है कि जलवायु परिवर्तन केवल विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि लोक–कल्याण और अस्तित्व का आधार है। उनके दिशा–निर्देशों में विकास की परिभाषा पूरी तरह बदल गई है। अब राज्य की हर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का 'कार्बन ऑडिट' अनिवार्य किया गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी परियोजना के निर्माण से पहले यह देखा जाता है कि उससे पर्यावरण को कितनी क्षति होगी और उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हम केवल पौधरोपण की खानापूर्ति नहीं करेंगे, बल्कि 'वृक्ष–संवर्धन' करेंगे। उनका लक्ष्य राज्य को 2030 तक कार्बन–तटस्थ बनाने की ओर अग्रसर करना है।

कुकरैल का कायाकल्प : कंक्रीट के जंगल में 'प्राण–वायु' का नया स्रोत

मुख्यमंत्री के हरित संकल्प का सबसे जीवंत और साहसिक उदाहरण कुकरैल वन क्षेत्र का पुनरुद्धार है। राजधानी के हृदय में स्थित यह क्षेत्र कभी उपेक्षा और अवैध अतिक्रमण का शिकार था। मुख्यमंत्री ने इसे 'लखनऊ के फेफड़ों' के रूप में पहचान दी और यहाँ एशिया की सबसे आधुनिक 'नाइट सफारी' और भव्य जैव–विविधता पार्क की नींव रखी। उन्होंने कुकरैल नदी की खोई हुई धार को वापस लाने और उसके किनारों को सघन वनों से आच्छादित करने का जो बीड़ा उठाया है, वह ऐतिहासिक है। यह परियोजना सिद्ध करती है कि यदि दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो लुप्त होती जल–धाराओं और मृतप्राय वनों को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। कुकरैल अब केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति और आधुनिक विकास के सह–अस्तित्व का वैश्विक मॉडल बन चुका है।

गोमती के तट पर 'हरित दीवार' का सृजन

मुख्यमंत्री की पर्यावरण नीति का एक और महत्वाकांक्षी अध्याय गोमती नदी के संरक्षण से जुड़ा है।

उन्होंने केवल नदी की सतह की सफाई के निर्देश नहीं दिए, बल्कि गोमती के किनारों को पौधरोपण के माध्यम से एक अभेद्य 'हरित दीवार' में बदलने का संकल्प लिया। नदी के तटों पर लाखों वृक्षों की यह कतार न केवल मृदा के अपरदन (Soil Erosion) को रोक रही है, बल्कि जल स्तर को बढ़ाकर नदी को स्वाभाविक रूप से स्वच्छ करने में मदद कर रही है। यह 'हरित दीवार' नगर के वायु प्रदूषण को सोखने वाले एक विशाल प्राकृतिक छलनी (Filter) के रूप में कार्य कर रही है।

वानर वन और जैव–विकास : एक मानवीय समाधान

बढ़ते शहरीकरण के कारण जब वन्यजीव बस्तियों की ओर आने लगे, तो मुख्यमंत्री ने बल–प्रयोग के बजाय वैज्ञानिक समाधान का मार्ग चुना। इसी सोच से 'वानर वनों' का जन्म हुआ। नगरों के बाहरी क्षेत्रों में फलदार वृक्षों से लदे विशेष वनों का विकास किया गया है। यह न केवल वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में भोजन उपलब्ध कराता है, बल्कि मानव–वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने का एक अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जैव–विकास (Biodiversity) ही पृथ्वी का असली कवच है। लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए उन्होंने विशेष 'हरित कार्यबल' का गठन किया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की कड़ियों को पुनः जोड़ रहा है।

नारी शक्ति : सौर ऊर्जा और धुएँ से मुक्ति

मुख्यमंत्री के विजन में पर्यावरण और नारी शक्ति एक–दूसरे के पूरक हैं। सौर ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन की योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को रसोई के जहरीले धुएँ से मुक्ति दी है। 'ऊर्जा स्वराज' की अवधारणा के तहत, अब ग्रामीण महिलाएं सौर संयंत्रों के माध्यम से न केवल बिजली पा रही हैं, बल्कि 'हरित उद्यमी' के रूप में जैविक खाद का निर्माण भी कर रही हैं। जब एक महिला का घर धुएँ से मुक्त होता है, तो उसका स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो अंततः एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है।

एक सच्चे नायक की पहचान उसकी करुणा से होती है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य में कोई भी मनुष्य भूखा न सोए, और न ही कोई बेजुबान पशु बेहाल रहे। अन्न सुरक्षा की योजनाएं जहाँ हर थाली तक भोजन पहुँचा रही हैं, वहीं गो–वंश के संरक्षण के लिए बने भव्य आश्रय स्थल मुख्यमंत्री के 'जीव–दया' भाव को दर्शाते हैं। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की चिंता भी जलवायु अनुकूलन का एक हिस्सा है, क्योंकि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रकृति की महत्वपूर्ण कड़ी है।

अंतहीन करुणा : भूख मुक्त समाज और पशु–कल्याण

एक सच्चे नायक की पहचान उसकी करुणा से होती है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य में कोई भी मनुष्य भूखा न सोए, और न ही कोई बेजुबान पशु बेहाल रहे। अन्न सुरक्षा की योजनाएं जहाँ हर थाली तक भोजन पहुँचा रही हैं, वहीं गो–वंश के संरक्षण के लिए बने भव्य आश्रय स्थल मुख्यमंत्री के 'जीव–दया' भाव को दर्शाते हैं। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की चिंता भी जलवायु अनुकूलन का एक हिस्सा है, क्योंकि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रकृति की महत्वपूर्ण कड़ी है।

बुंदेलखंड की प्यासी माटी का 'अमृत' अभिषेक

बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने 'अमृत सरोवर' के माध्यम से जल क्रांति ला दी है। ''वर्षा की हर बूंद को ग्राम की सीमा के भीतर ही संचित करो''–इस मंत्र ने पथरीली धरती का भाग्य बदल दिया है। 'खेत का पानी खेत में' और 'मेड़ पर पेड़' के संकल्प ने न केवल सिंचाई की व्यवस्था सुधारी है, बल्कि भूजल स्तर को भी ऐतिहासिक ऊंचाई दी है। अब यहाँ के तालाब केवल जल के स्रोत नहीं, बल्कि गाँव की समृद्धि के केंद्र बन गए हैं।

वायु गुणवत्ता और प्रदूषण मुक्त नगरीय जीवन

नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण के दानव को वश में करने के लिए मुख्यमंत्री ने 'ग्रीन मोबिलिटी' का सहारा लिया है। सड़कों पर दौड़ती विद्युत–चालित बसें और निर्माण स्थलों पर 'धूल–नियंत्रक यंत्रों' की अनिवार्यता इसका प्रमाण है। उद्योगों के लिए 'अपशिष्ट जल का शून्य बहाव' (Zero Liquid Discharge) अब अनिवार्य नियम है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है–''मुनाफा कमाओ, पर प्रदूषण की कीमत पर नहीं।''

नई पीढ़ी के 'जलवायु योद्धा' और चेतना का संचार

मुख्यमंत्री का मानना है कि वास्तविक क्रांति विद्यालयों के बस्तों से आरम्भ होगी। उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को केवल रटने का विषय नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बनाया है। आज हर सरकारी विद्यालय का विद्यार्थी 'जैविक खाद' और 'जल संचयन' के महत्व को समझता है। मुख्यमंत्री स्वयं समय–समय पर बच्चों के साथ 'पर्यावरण संवाद' करते हैं, जिससे भविष्य के 'हरित प्रहरी' तैयार हो रहे हैं।

सुरक्षित विरासत की ओर बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री के ये दिशा–निर्देश और योजनाएं केवल निर्वाचन जीतने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री स्वयं अक्सर कहते हैं– ''प्रकृति हमारी माता है, और उसका संरक्षण हमारा राजधर्म है। हम धरती से उतना ही लें जितना उसे लौटा सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक समृद्ध और हरित भारत में सांस ले सकें।''

जब इतिहास लिखा जाएगा, तो वह केवल आर्थिक विकास की दर नहीं पूछेगा, वह यह भी पूछेगा कि आपने अपनी संतानों के लिए कितनी स्वच्छ वायु, कितना शुद्ध जल और कितनी जैव–विविधता छोड़ी। मुख्यमंत्री का यह 'हरित पथ' आज पूरे भारत को एक नई दिशा दिखा रहा है। ◆

मो. : 9119666674

(लेखिक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

आर्थिक संबल बन रहा काला नमक चावल

–यशोदा श्रीवास्तव

अपनी खुशबू से देश–विदेश में खास पहचान वाले काला नमक चावल को पुनर्जीवन देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की जितनी भी सराहना की जाय कम है। एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में सिद्धार्थनगर जिले के इस महकदार चावल को शामिल कर न केवल इसकी महत्ता को अंतरराष्ट्रीय फलक तक फैलाया गया, लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके गौतमबुद्ध के इस प्रसाद को फिर से नया जीवन मिल गया।

बता दें कि यूपी के पूर्वांचल में स्थित सिद्धार्थनगर जिले की पहचान दुनिया में दो कारणों से ही है। एक तो यहां स्थित भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु से, दूसरे यहां की खास उपज काला नमक धान से। जब रूस, चीन, जापान, थाईलैंड,वर्मा में भारत को लेकर कोई चर्चा होती है तो सिद्धार्थनगर जिले का नाम आ ही जाता है। यद्यपि कि यह चर्चा भगवान बुद्ध को लेकर होती है लेकिन जब बुद्ध चर्चा में होते हैं तो काला नमक धान की चर्चा स्वाभाविक है क्योंकि काले रंग के इस धान को बुद्ध का प्रसाद माना गया है। काला नमक धान के चावल की खुशबू अमेरिका, थाईलैंड और जर्मनी के अलावा दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचती है।

योगी सरकार की पहल से कृषि क्षेत्र की इस प्रजाति के दिन बहुर चुके हैं। तमाम झंझावतों की वजह से जो किसान इस खास किस्म के धान की खेती से मुंह मोड़ने लगे थे, अब वे इसके व्यवसाय से जुड़ कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले की खास उपज काला नमक धान की खुशबू अब पूरे इलाके में फैल रही है। अंग्रेजी शासन में बर्डपुर के अंग्रेज जमींदार ने इस धान के महत्व को समझा था। इसके संरक्षण और बढ़िया उपज के लिए उसने नहरों का जाल बिछा दिया था। इस धान की बढ़िया पैदावार के लिए खेतों में हमेशा पानी की उपलब्धता जरूरी है। अंग्रेज जमींदार विलियंस पेपे ने सिद्धार्थनगर जिले के उत्तर में कई सारे जलाशयों का निर्माण कराया था। इन जलाशयों से नहरों और चकनालियों का ऐसा निर्माण कराया गया था कि पानी सीधे खेत में पहुंचे। अंग्रेज जमींदार इस धान से उत्पन्न चावल को ब्रिटेन भेजते रहे। आजादी के बाद कुछ सालों तक तो इस धान का उत्पादन जारी रहा लेकिन धीरे–धीरे यह उपेक्षा का शिकार होता गया। इस खास किस्म के धान संरक्षण की आवाज विधानसभा और संसद में हमेशा उठती रही लेकिन इसकी सुधि नहीं ली गई। 2017 में

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस धान और इसके खुशबूदार चावल के महत्व को समझा और इसे इस जिले के खास उत्पाद की श्रेणी में शामिल कर इसके संरक्षण और बाजार की व्यवस्था की। मजे की बात यह है कि इस धान पर कभी अनुसंधान तक नहीं हुआ और न ही इसकी प्रजातियों को विकसित करने का ही प्रयास हुआ। 2018 में जीआई टैग के बाद गोरखपुर में इसका अनुसंधान शुरू हुआ तो काला नमक धान की अन्य प्रजाति विकसित हुई। इसी के साथ 170 दिनों में पैदा होने वाले इस धान की खेती का दायरा भी बढ़ा। पूर्व में अकेले सिद्धार्थनगर जिले की उपज के रूप में विख्यात इस धान की खेती अब गोरखपुर मंडल से लेकर बाराबंकी तक होने लगी है। लेकिन एक बात है कि जो खुशबू सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल में है वैसी खुशबू अभी भी अन्य जिलों में उत्पादित काला नमक चावल में नहीं है। इसीलिए सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल अभी भी खास बना हुआ है। इस जिले में उत्पादित काला नमक चावल न केवल अन्य जिलों में उत्पादित चावल की अपेक्षा अधिक पौष्टिक है,यह शुगर–फ्री भी है। यहां के चावल की मुलायमियत और दूर तक बिखेरने वाली खुशबू का कोई जोड़ नहीं है।

> **यूपी के पूर्वांचल में स्थित सिद्धार्थनगर जिले की पहचान दुनिया में दो कारणों से ही है। एक तो यहां स्थित भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु से दूसरे यहां के खास उपज काला नमक धान से। जब रूस, चीन, जापान, थाईलैंड,वर्मा में भारत को लेकर कोई चर्चा होती है तो सिद्धार्थनगर जिले का नाम आ ही जाता है। यद्यपि कि यह चर्चा भगवान बुद्ध को लेकर होती है लेकिन जब बुद्ध चर्चा में होते हैं तो काला नमक धान की चर्चा स्वाभाविक है क्योंकि काले रंग के इस धान को बुद्ध का प्रसाद माना गया है। काला नमक धान के चावल की खुशबू अमेरिका, थाईलैंड और जर्मनी के अलावा दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचती है।**

किसान पूर्व में इस धान की खेती केवल अपने या कुछ रिश्तेदारों के लिए करते थे। शादी विवाह या ऐसे ही किसी खास मौकों पर इसका इस्तेमाल होता था। चूंकि इसकी खेती में श्रम और पैसा अधिक लगता है, दूसरे महंगा होने के नाते इस चावल के खरीददार नहीं होते थे, इसलिए किसान इस धान की खेती से मुंह मोड़ते गए। सिद्धार्थनगर जिले में इस धान की खेती का रकबा पहले दस हजार हेक्टेयर के आसपास था। बाद में तमाम विसंगतियों के चलते दो चार हजार हेक्टेयर तक सिमट गया। अब जब योगी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया तो किसान प्रेरित हुए और इस खेती की ओर उन्मुख भी हुए। आज के वक्त में अकेले सिद्धार्थनगर जिले में करीब 15–20 हजार हेक्टेयर से अधिक के रकबे में इसकी खेती हो रही है। और खेती ही नहीं हो रही, कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी स्थापित हो गए जो इस चावल की खरीदारी कर दूर दूर तक सप्लाई भी कर रहे हैं। आज की तारीख में यहां काला नमक चावल का भाव 13 हजार रुपए कुंतल है और ढूंढे नहीं मिल रहा। मसलन जिस चावल के उत्पादन से किसान भाग रहे थे आज वह यहां किसानों की समृद्धि और आर्थिक मजबूती का आधार बन गया है। ◆

मो. : 9918955583

(लेखक सीनियर जर्नलिस्ट हैं)

मिशन शक्ति
शक्ति से समृद्धि
नारी
उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी
नवनिर्माण के 9 वर्ष
सुरक्षा से समझौता नहीं
सभी थानों में 'मिशन शक्ति' केंद्र
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
26.81 लाख+
बेटियां सशक्त
निराश्रित महिलाओं को पेंशन
लखपति दीदी योजना
18.55 लाख+
महिलाएं बनीं लखपति
महिला श्रम बल भागीदारी
13% से बढ़कर 36%
1 करोड़+
ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर
मेधावी छात्राओं को स्कूटी का उपहार
कामकाजी महिलाओं के लिए
श्रमजीवी महिला छात्रावास
महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड
ब्याज मुक्त ऋण
10,400+
स्टार्ट-अप का नेतृत्व
विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए विशाल सिंह, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित, सम्पादक—चन्द्र विजय वर्मा।